I request the Minister of Supply and Rehabilitation to make a statement in this regard.

13.02 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83— *Contd.*

MINISTRY OF COMMERCE—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Commerce. Shri Chandradeo Prasad Verma was on his legs.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो एक वस्त्र नीति की घोषणा संसद में ही, दोनों सदनों में की थी, उसके संबंध में क्या काम हुआ है अभी तक । एक वर्ष में क्या उसके बारे में प्रगति हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हालांकि इसके पहले उप-मंत्री महोदय ने इसके ऊपर भाषण किया है लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा । बहुत विस्तार में वह नीति है, मैं उस सब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उसमें कुछ मुद्दों की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । घोषणा के मुख्य मुद्दों में से कुछ ये हैं । छोटे बुनकरों तथा इनसे संबंधित अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसका विकास करना, कमजोर वर्गों के लिए सस्ते कपड़े का वितरण करना, मानव निर्मित रेशे तथा यार्न में वृद्धि करना, हथकरघा क्षेत्र में बेकार पड़े करघों को पुनः चालू करना, अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण करना, उचित दामों पर यार्न देना, हथकरघों द्वारा पालियेस्टर तथा गैर-सूती वस्त्रों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण पर कड़ा नियत्रण रखना क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में बड़ा गौलमाल होता है और गरीब व्यक्तियों को वह मिल नहीं पाता । उचित कीमत पर रूई उपलब्ध कराना, आदि । ये सब कार्य सरकार द्वारा हो रहे हैं । जो नीति घोषित हुई थी, क्या सरकार उस पर चल रही है । स्पष्ट है कि इस नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है ।

भारत में लगभग 35 लाख हथ-करघे हैं । मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और मैं यह समझता हूं कि इस के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है । हथकरघा चलाना बहुत कठिन काम है । रातदिन यदि हथकरघे में पूरा परिवार भी लगा हुआ है, तब भी उसको खाने भर की मजदूरी नहीं मिल पाती है । इसलिए इसमें कुछ विकास करने की आवश्यकता है । जो इस का विकास नहीं हो रहा है, उसी कारण इसमें लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा है इसलिए और नई पीढ़ी के लोग इसमें आ नहीं रहे हैं और यह उद्योग टप्प पड़ता चला जा रहा है । इन लोगों को जो सहायता दी जा रही है, अफसर और बिचोलिए करीब-करीब वह सारा पैसा खा जाते हैं और इन लोगों तक पहुंचते-पहुंचते वह सारी सहायता समाप्त हो जाती है । इसलिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । और वस्त्र उद्योग के लिए एक ओर स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है । जो लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग इस धंधे में लगे हुए हैं उन लोगों को स्पष्ट रूप में

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा]

कहना चाहिए कि विदेशों में अपना बाजार खोजो और खोज कर उसका विकास करो । उसके सारे काम, सप्लाई वैगरह सब तुम्हारे जिम्मे रहेंगें । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, हथकरघा तथा पावर लूम बोर्ड इन सब को जो देश में कपड़े की आवश्यकता है, उसके अनुसार काम करना चाहिए । गांवों में बसने वाले लोगों, भारत में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस आधार पर कपड़ा दिया जाएगा, इस आधार पर कपड़े का वटवारा हो सकेगा । मैं समझता हूं कि यह उचित काम होगा, अन्यथा नहीं होगा ।

अब में रेशम उद्योग की तरफ आना चाहता हूं । प्राकृतिक रेशम की चार किस्में हैं—शहतून, ऐरी, तस्सर और मूंगा । मूंगे के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है । तस्सर में भारत का दूसरा स्थान है और शहतून में पांचवा स्थान है ।

भारत सरकार यदि चाहे तो इन उद्योगों को बहुत आगें बढ़ा सकती है। इसके लिए सर्व प्रथम आवश्यक है कि अच्छे अनुसंधान की व्यवस्था हो। अभी अनुसंधान नहीं हो रहा है । उत्पादन थोड़ा जरूर बढ़ा है लेकिन जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रहा है । किस्म अच्छी नहीं निकल रही है । इसमें ज्यादा रेशम बर्बाद होता जा रहा है । उत्पादक तथा बुन कर को कम पैसा मिल रहे हैं इस में भी बिचौलिए और व्यापारी अधिक पैसा खाए जा रहे हैं। इस बात पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बिचोलिये और व्यापारी अधिक मुनाफा न खाएं और ज्यादा मुनाफा उनको मिलना चाहिए जो मेहनत करके इसको तैयार करते हैं ।

इसका उत्पादन जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए वह नहीं हो रहा है । बोर्ड में अनेकों प्रकार के झगड़े हैं । अभी इसका एक्ट आया था । उसमें संशोधन भी हुआ है । माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला था । बोर्ड में निश्चित रूप से झगड़े हैं और इन झगड़ों के चलते यह सारा व्यापार चौपट हो रहा है । इस में सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिए था । इसकी जांच भी की जानी चाहिए थी ।

नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट 31 जनवरी, 1976 को दी थी । उसमें कहा गया है :—

"The Central Silk Board should come under the Ministry of Agriculture and Irrigation and be reconstituted with the representatives from the States, the ICAR, the Union Ministries of Agriculture, Industrial Development, Commerce and All India Khadi and Village Industries Commission, etc."

इन सब को मिल करके एक होना चाहिए और यह एग्रीकल्चर में सीधे जाना चाहिए । इसमें पुनः कहा है:—

"The Secretary of the Central Silk Board should preferably be technically qualified and have the status of a Joint Secretary to the Government of India."

ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं चल रहा है । रिपोर्ट आ गई है लेकिन पड़ी हुई है । सरकार के दफ्तर में इसके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। रेशम उद्योग निश्चित रूप से कृषि पर आधारित है । इस में कुल 35 लाख लोग लगे हुए हैं जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है । राष्ट्रीयकृत बैंक सहायता नहीं कर रहे हैं ।

एक खबर है कि वाराणसी में बुनकरों को काम नहीं मिल रहा है।

सरकार ने जो जवाब दिया है वह बड़ा आश्चर्यजनक है । उपाध्यक्ष महोदय, इसको देखकर हम लोगों को लज्जा आती है । सरकार ने जवाब दिया है कि "जब 50 टन रेशम चीन से आयात होगा तब उन्हें दिया जाएगा ।" यह सचमुच में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है, इसके लिए शीघ्र प्रबंध किया जाए । वहां मजदूर बेकार बैठे हुए हैं । वहां का रेशम कारोबार दुनियां भर में विख्यात है, सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इस ओर कुछ नहीं किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो रहा है और मेरे अन्य मित्र इन पर प्रकाश डालेंगे । मैं यही चाहता हूं कि इस पर तेजी से कार्यवाही होनी चाहिए और जो यह रिपोर्ट है, उसके अनुसार काम होना चाहिए ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री श्री पाटिल साहब की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से और साहस के साथ एक साहसिक कदम निर्यात-आयात नीति के संबंध में इस देश की आर्थिक नीति को अधिक मजबूत, सुदृढ और उदार बनाने के लिये उठाया है । नई आयात नीति की घोषणा के अन्तर्गत बहुत सी सुविधायें दी गई हैं और वे इस दृष्टि से दी गई हैं कि हमारे देश के अन्दर उत्पादन क्षमता बढ़े और उत्पादन बढ़ने से हमारी आर्थिक स्थिति में मजबूती आए ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि विश्व की 15 प्रतिशत जनता या 15 प्रतिशत आबादी, विश्व की 75 प्रतिशत दौलत का अपने तरीके से इस्तेमाल करती है या उस पर अपना आधिपत्य रखती है और विश्व के 75 प्रतिशत नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन करके उसको इंडस्ट्रियल या दूसरे तरीके से तैयार करके विश्व की 15 प्रतिशत आबादी उसका लाभ उठाती है और उसका सीधा लाभ उन्हीं को जाता है और यही कारण है कि आज विश्व की 15 प्रतिशत आबादी अलग संपन्नता लिये हुए है और वह एक विश्व का अलग वर्ग बनी हुई है ।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्व ट्रेड को और इसके साथ-साथ अपने देश के ट्रेड को, चाहे वह इंपोर्ट हो, या एक्सपोर्ट हो, देखें तो हमको प्रतीत होगा कि नार्थ यूरोपियन कंट्रीज, यू० एस० ए०, जापान, ये ऐसे मुल्क हैं जो आज की डेवलपिंग कंट्रीज के दो-तिहाई प्राइमरी प्रोडक्टस् को खरीदते हैं और वही आज भी हमारे मार्केट है और यही कारण है कि उनकी मर्जी पर या उनके द्वारा तय किये गये मूल्यों को स्वीकार करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिये जरूरी हो जाता है, आबलीगेटरी हो जाता है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा, कि जहां वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है, यह एक बड़ा गंभीर विषय है । वाणिज्य मंत्रालय देश की आर्थिक नीति से बहुत गहरा संबंध रखता है, इतना संबंध किसी दूसरे मंत्रालय का नहीं है और वास्तव में यह मंत्रालय अपने आप तक देश के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, उसके साथ भी इसका अपने-आप में संबंध है ।

सारा विश्व इस बात को जानता है कि वर्ष 1981 वर्ल्ड-ट्रेड के लिये स्टेगनेंसी का साल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड में कोई तरक्की नहीं हुई है, जबकि वर्ष 1980 में एक प्रतिशत वृद्धि वर्ल्ड ट्रेड में हुई थी और सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि इस वर्ष 1981 में डेवलपिंग कन्ट्रीज का 13 प्रतिशत प्राइमरी प्रोडक्ट्स

[श्री राम सिंह यादव]

डेवलप्ड कंट्रीज को कम निर्यात किया गया है। हिन्दुस्तान डेवेलेपिंग कंट्रीज में आता है। वह भी प्राइमरी प्रोडक्टस् दूसरे देशों को भेजता है। मुझे प्रसन्नता है कि इन विकासशील देशों ने सबसे पहला एक साहसिक कदम यह उठाया है निर्यात के संबंध में कि इंडस्ट्रीयल मैनुफ़ैक्चर्ड गुड्स का भी निर्यात किया है। डेवेलेपिंग कंट्रीज की मैनुफ़ैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ती जा रही है। उनकी वहां खपत बढ़ती जा रही है।

1981 के वर्ष से एक और भी संकेत मिलता है। इस के लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता हूं। वर्ल्ड ट्रेड में एग्रीकलचरल प्रोड्यूस के महत्व को उस ने स्वीकार किया है। वर्ल्ड में एग्रीकलचरल प्रोड्यूज के लिये सबसे अच्छा मार्किट है। अब आप देखें कि वर्ल्ड एक्सपोर्टस् में एग्रीकलचरल प्रोड्यूस का ग्रोथ रेट पांच प्रतिशत बढा है जबकि इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स का केवल तीन प्रतिशत बढ़ा है। इससे सिद्ध होता है कि आपके पास एवेन्यूस है एक्सपोर्ट को बढाने के। आपके पास एग्रीकलचरल सैक्टर्स हैं, एग्रिकलचरल कमोडिटीज हैं, और आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस क्षेत्र के इस ऐवेन्यू को स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि आपने उस पर और ज्यादा कंसेंट्रेट करने की बात कही है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो निर्यात के मामले में आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी।

वर्ल्ड ट्रेड के जो हालात हैं और जो प्रतिकूलतायें हैं उन में भारत को बहुत बड़ी कोशिश अपने निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में करनी पड़ी है। उस में कुछ नीतिगत बातें भी हैं जिनका बजट में भी जिक्र किया गया है और मंत्रालय की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। सब से बड़ी नीति की बात इकोनोमिक कोओप्रेशन की है। वह डेवेलेप्ड कंट्रीज से नहीं मिल रही है। सब से बडी हिन्ड्रेंस वाली बात पालिसी आफ़ प्रोटेक्शनिजम की है जिस की वजह से डेवेलेप्ड कंट्रीज अपने आप को एलूफ़ फ़ील करते हैं। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने इंटरनेशनल कान्फ्रेंसिस में कहा है कि जब तक विश्व के अन्दर इकोनोमिक कोआपरेशन नहीं बढ़ेगा तब तक डेवेलेपिंग कंट्रीज कभी भी आगे नहीं आ सकेगें और विकसित देशों के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकेंगीं। लेकिन हम विकसित देशों के मुखापेक्षी बने रहे यह भी ठीक नहीं है। वे हमें इकोनोमिक कोओप्रेशन दें तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड तरक्की करे और उसी के ऊपर आधारित रह कर हम काम करें यह ठीक नहीं है।

मेरा निवेदन है कि कुछ आइटम्ज है जिन को हम ट्रेडीशनल एक्सपोर्ट आइटम्ज कहते है और मुझे दुख है कि आज इन आइटम्ज के बारें में भी जिन पर उसकी हजारों साल से मनोपोली रही है, वह अपनी उस मौनोपोली को भी खोता जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड में टैक्सटाइलज, टैक्सटाइल फैब्रिक्स, रा काटन वगैरह के मामले में उसका बहुत बड़ा भाग रहा है। रा काटन के मामले में हमारी एक्सपोर्ट 71 परसेंट कम हो गई है। स्टील और आयरन में 15 प्रतिशत कम हो गई है। काफी में शायद 45 परसेंट कम हो गई है। काफी के मामले तो इंटरनैशनल मार्किट में आपके कहीं

पैर ही नहीं जम रहे हैं। इन मामलों में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। बजट में काफी प्लांटेशंज, टी प्लांटेशंज, कार्डिमम, रबड़ आदि के ऊपर आपने वैल्थ टैक्स को भी समाप्त कर दिया है। उसके बावजूद आपने कोई संकेत नहीं दिया है वर्ल्ड ट्रेड में काफी, चाय, टैक्सटाइल, टैक्सटाइल फैब्रिक्स, रा काटन, आयरन और स्टील के मामले में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड मार्किट को किस तरह से कैप्चर आप कर सकेंगे। इसका कोई इंडिकेशन 8–9 महीने की रिपोर्ट में नहीं है, अप्रैल से दिसम्बर तक की जो प्रगति की रिपोर्ट आपने दी है, उस में कोई संकेत नहीं है। केवल इतना संकेत दिया है कि पिछले वर्ष जो एक्सपोर्ट ग्रोथ 26 परसेंट कम रहा इस वर्ष नौ महीने के अन्दर वह 11.9 प्रतिशत ही कम रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिला कर 37–38 परसेंट ग्रोथ रेट कम रहा है। इस तरीके से आप ऐक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट की किस तरह से आगे कर सकेंगे? आप काबू नहीं कर सकते हैं? जब तक किसी देश के अन्दर ऐक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाते हैं और इम्पोर्ट को कम नहीं करते हैं तब तक इकोनामी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। इन दोनों के अन्दर बैलेंस को कायम नहीं रख सकते हैं। पिछले दो साल से बराबर ट्रेड गैप बढ़ रहा है। 1980–81 में ट्रेड गैप 5,790 करोड़ रु० का था और इस समय पिछले 8 महीने में 3,523 करोड़ रु० का है। इसको किस तरह से पूरा करेंगे, कौन से क्षेत्र को आप लेंगे, ऐसी कोई इंटेशन आपकी रिपोर्ट या काम से नहीं मिलती है। यह बात सही है कि जब तक आप मार्केट को ऐक्सप्लोर नहीं करेंगे और आप नहीं देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनकी देश के अन्दर खपत होते हुए भी बाहर भेज सकते हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि फोरेन एक्सचेंज लाना है और अपने ट्रेड बैलेंस को बनाये रखना है, तब तक काम नहीं चलेगा। कई बार कहा गया ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में एक सिस्टेमैटिक तरीके से नीति बनाइये। ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस तरह ऐक्सपोर्ट करेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। हमारा कृषि प्रधान देश है जिसमें, 80 प्रतिशत लोग खेती पर रहते हैं उस देश के अन्दर भी मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आपने 1980–81 में 58.05 करोड़ का गेहूं मंगाया है। 1.84 करोड़ का राइस मंगाया है, 28.9 करोड़ के अन्दर सिरियल्स और 26.1 करोड़ के सीरियल प्रोपरेशन्स मंगाये हैं और मिल्स और क्रीम भी 52.97 करोड़ का इम्पोर्ट किया है। जब हम चावल और गेहूं के बारें में कहते है कि सेल्फ सफिशियेंट हैं और मिल्क के बारें में कहते है कि आवश्यकता नहीं है मंगाने की फिर इनका इम्पोर्ट पर इतना करोड़ों रू० क्यों खर्च किया जा रहा है? आपको गेहूं मंगाने की आवश्यकता नहीं थी, जो वेजिटेबिल्स और फुट्स है आपने कैशूनट्स का इम्पोर्ट किया है, हीरे जवाहरात का इम्पोर्ट किया है। ऐसे आइटम्स को जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो लग-

[श्री रामसिंह यादव]

जरी गुड्स है उनको आपको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिये । मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे आइटम्स है जिनके इम्पोर्ट को आप कम नहीं कर सकते हैं, जैसे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जितना इम्पोर्ट पर खर्च कर रहे हैं उसका 45 परसेंट केवल आयल पर खर्च होता है : लेकिन और जो दूसरे आइटम्स है जिनके बगैर भी काम चल सकता है उनको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिये आप कपड़ा भी इम्पोर्ट कर रहे हैं । अगर आप इनफीरियर क्वालिटी का कपड़ा पहनते है तो देश को नुक्सान नहीं होगा । इम्पोर्ट को कम करने के लिये देश के लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है । ब्लेड के कारखानों के लिये बाहर से कोलीबरेशन करने की क्या जरूरत है । आपने कहा दिल्ली में एशियाड गेम्स के समय पेड़ों पर पानी छिड़कने के लिये इटली से फव्वारे मंगाये जायेंगे । इसकी क्या जरूरत है । ऐक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बैलेंस रखे की आपकी भारी जिम्मेदारी है । तो किसी घर में, घरवाला बाहर से खरीदता ही रहे और अपनी कुछ चीज बनाकर बाहर भेजेगा ही नहीं जरूरी बात है कंगाल होगा, उसकी पावर्टी बढ़ेगी । इसके लिये जरूरी है कि हम इम्पोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावें । तभी आप पावर्टी को कम करने में सफल कदम उठा सकें ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में जो आपने नीति बनाई हुई है, इससे आपको कुछ नुक्सान भी हो रहा है और सबसे ज्यादा नुक्सान यह है कि काफी में जहां 45 परसेंट का आपका मायनस है, मसाले में भी 29 परसेंट मायनस है । इसी तरह काटन में 71 परसेंट आयरन एंड स्टील में 5 परसेंट, काटन फैबरीक्स में 8 परसेंट, जूट मैन्युफैक्चरिंग में 13 परसेंट, मैंटल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सक्लूडिंग आयरन एंड स्टील 15 परसेंट मायनस है । तो जो आपकी मेजर आइटम्स हैं, जिनको मैन स्टे कामोडिटीज कहते हैं, एक्सपोर्ट के नुक्तेनजर से उनका एक्सपोर्ट आपका गिर रहा है और लगातार उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है । यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है, जिसको आपको गंभीरता से लेना है और आपको सोचना है कि कौन से मार्केट मिल सकते हैं, मिडिल ईस्ट के या दूसरे कंट्रीज के अच्छे मार्केट मिल सकते हैं । इनको हमें देखना और तलाश करना होगा । इसे देखने और तलाश करने के लिये आपके मंत्रालय की रिपोर्ट में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है । जो कि बहुत जरूरी है । सबसे अधिक पैसा आपको इस पर खर्च करना है, इसकी रिसर्च करनी है और इसे डेवलप करना है ।

इम्पोर्ट के बारे में जैसा मैंने कहा कि पी० एल० ओ० पर 5586.87 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है और नान पी एल ओ पर 6847.71 करोड़ का खर्चा किया है । मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है कि जो फर्टिलाइजर पिछले साल इम्पोर्ट किया गया

उसमें से कितना आपने खर्च किया ? मैंने कल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है कि जो फर्टिलाइजर आपने मंगाया उसका ज्यादा हिस्सा स्टाक में पड़ा है उसको किसान ने उठाया नहीं, उसके रेट हाई थे और दूसरे कारण भी थे। जब तक आप अपनी खुद की डिमांड को स्टडी नहीं करेंगे, रिक्विजीशन किन किन डिपार्टमैन्टस ने दी है, इंडैट दिया है, अगर फर्टिलाइजर आपके यहां पड़ा रहता है, कोई इस्तेमाल नहीं होता है तो जो फारेन एक्सचेंज आपने उसमें इन्वैट कर दिया उससे कोई लाभ नहीं होता है, सिवाय नुक्सान के कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि फर्टिलाइजर पर जितना एमाउन्ट इन्वैस्ट किया है, यह ठीक है कि फर्टिलाइज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले साल आपका फर्टिलाइजर सरप्लस हुआ और मुल्क में उसकी कंजम्पशन गिरी है। यह भी ठीक है कि अबकी बार फर्टिलाइजर की कुछ मदों पर वित्त मंत्री नें 100 परसेंट एग्जम्पशन दिया है ड्यूटी का। वह एक सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि कौन सी मदों पर आप इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं ?

इसके अलावा वेजीटेबल आयल को मंगाने पर आपने 567.78 करोड़ रुपये लगाये है, आयरन एंड स्टील पर आपने 779.20 करोड़ रुपये लगाये हैं। मशीनरी एंड ट्रांस्पोर्ट इक्विपमेंट पर 1572.74 करोड़ रुपये 1980-81 में खर्च किया है। इस तरह से जितनी भी इम्पोर्ट की मदें हैं उन पर आपका खर्चा बढ़ा है, किसी में कम नहीं हुआ। यह मैं मानता हूं कि ऐसी मदें हैं, जैसी मशीनरी का इम्पोर्ट आपने टक्नोलोजी को डेवलप करने के लिये किया है। 100 परसेंट जो गुड्स तैयार करके बाहर भेजते है, जो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड गुड्स है उनके लिये आप टेक्नोलोज़ी इम्पोर्ट करते है, मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं, उसमें तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो ऐसी मशीनरी है जो यहां मिल सकती है, लेकिन आप यह कहे कि एफीशियेन्ट तरीके की होगी, इसके लिये आपको चैक करना होगा, स्पेशल सेल कायम करने होंगे। ओंपन तरीके से सभी को इजाजत देते चले जायेंगे तो आप इम्पोर्ट को किसी भी तरीके से कम कर सकेंगे। आपको थ्रस्ट इस बात पर होनी चाहिये कि इम्पोर्ट कैसे कम करें।

इन 8, 9 महीने में इम्पोर्ट 11.9 परसेंट कम हो गया है, इस तरह के इंडोकेशन्स आपने दिये है कि पिछले साल से यह कम हुआ है। लेकिन पिछले साल भी यह आपका ऊपर जा रहा था, 26 परसेंट का आपका खुद का रिकार्ड है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये आपको कुछ नीतियां निर्धारित करनी जरूरी हैं। उसमें सब से पहली आवश्यकता यह है कि मंत्री महोदय को अपनी टेक्सटाइल पालिसी पर दोबारा सोचना पड़ेगा। हिन्दुस्तान अपने निर्यात के लिये काटन और टेक्सटाइल फैब्रिक्स पर डिपेंड करता है। इस नीति के मजबूती

[श्री रामसिंह यादव]

के साथ स्वीकार करना है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है।

हैंडीक्राफ्ट्स पार बहुत कम ध्यान दिया गया है। गुराजस्थान, उड़ीसा, तामिलनाडू गुजरात और नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैंडीक्राफ्टस की बाहर के मार्किट में बहुत बड़ी मांग है। उन्हें जितना अधिक बढ़ावा दिया जायेगा और जितने अधिक इनसेन्टिव्ज दिये जायेंगे उतना ज्यादा फारेन एक्सचेंज हम ले सकते हैं। यह एक ऐसा फील्ड है जो हमें अधिक से अधिक फारेन एक्सचेज दे सकता है। इसका मार्केट भी आसानी से मिल सकता है। लेकिन एनुअल रिपोर्ट से इस बारे में कोई विशेष प्रयत्न जाहिर नहीं होता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे।

जहां तक कृषि उत्पादन—वेजीटेबल्ज और फ्रूट—का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से कहा जाता है कि डोमेस्टिक कनजम्पशन को देख कर उनका निर्यात किया जाता हैं। अगर डामेस्टिक कनजम्पशन को कम करना जरूरी हो, अगर सब्स्टीट्यूट्स को स्तेमाल किया जाए —जैसे सब्जी को दालों से सब्स्टीट्यूट किया जाये—तो वह करना चाहिये लेकिन अगर किसी भी कामोडिटी का निर्यात करने से फारेन एक्सचेंज मिल सकता है, तो उसका निर्यात जरूर करना चाहिये। एक्सपोर्ट के लिये यह नीति कारगर नहीं हो सकती कि अगर हमारे पास कोई सरप्लस कामोडिटी होगी, तभी उसे एक्सपोर्ट करेंगे। सरकार को अपने पर और नेशन पर कुछ न कुछ रेस्ट्रेंट लगाना होगा और किसानों को कुछ इनसेन्टिव्ज भी देने होंगे। किसान सेव, बेनाना या आम पैदा करता है, अगर वह ज्यादा पैदा हो जाता है, तो उसके भाव गिर जाते हैं। सरकार उन्हें बाहर नहीं भेजती है। सरकार को उनके लिये बाहर को मार्केट तलाश करनी चाहिये, ताकि देश को फारेन एक्सचेज मिले ;

लेदर, फुटवियर और लेदर मैनुफैक्चर का एक्सपोर्ट भी गिरा है। इस साल सरकार ने थोड़ा बढ़ावा दिया है, लेकिन दो साल से उसका ट्रेड डाउनवर्ड है। इसमें हमारा देश ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमा सकता है, इसलिये इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस पैदा होता है। जो मुल्क से खरीदना चाहते हैं, हम उन्हें वह चावल एक्सपोर्ट करें और फारेन एक्सचेज प्राप्त करें। हम अपने देश में आर्डिनेरी क्वालिटी या लोअर क्वालिटी का चावल कन्जूम करें और अपनी इकानोमी को मजबूत करने के लिये अच्छी क्वालिटी के चावल को एक्सपोर्ट कर के फारेन एक्सचेज हासिल करें, इसमें गुरेज नहीं करना चाहिये, बल्कि इसको डेवलप करना चाहिये।

आप बहुत योग्य राज्य मंत्री हैं। आपकी योग्यता में किसी को शको-शुबहा नहीं है। आप बहुत मेहनती भी हैं। लेकिन आपका महकमा एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आपको सारे वर्ल्ड से कम्पीट करना है। जब तक आप रात के 12 बजे तक वर्ल्ड मार्केट के ट्रेड्ज को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप मंत्रालय को सही गाइडेंस नहीं दे सकते। इस बारे में अधिक से अधिक मेहनत और काम की जरूरत है। हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, उसे कम करने की जरूरत है।

इन सुझावों के साथ मैं इस मंत्रालय की डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Mr. Deputy-Speaker, Sir, recently on behalf of the Government of India, a new import policy has been announced. This import policy does not come in a vaccum;

it comes in the background of a specific situation, and it has to be judged in that background. That background is a background of, I should say, almost crippling dimensions of a trade deficit, which is mounting from year to year, and which, according to this book, has reached a figure of Rs. 5790.30 crores for 1980-81. This Report of the Ministry also says that exports have also been rising; but while exports have been going up by 4 percent, the Report admits that the imports have gone up by 39 per cent.

So, the dimension of the imbalance is very clear and it is admitted...).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V PATIL): It is for the past; not for the present . This 39 per cent import is for 1981.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Yes. It is also stated. And I know the Minister—because it is also indicated in the book—is going to say that we are entering into a new phase in which exports are going up in a big way. But here it is stated in this book that there are certain basic factors, not temporary, not fluctuating, but rather, I should say, long term basic factors, which are acting as a brake on the growth of our exports, which are hampering our exports. So, if this is his argument when he replies that exports are going to look up and all that, he will have to tell us also from the study of the global phenomena how those factors which they admit are preventing exports—and not only our exports, but exports of almost all the developing countries—from going up, are going to be countered? What is all this hullabaloo about North-South struggle going on in the world, this whole business of fighting for a new economic order for which the Government of India took an initiative recently and held, what is called, South-South-Conferance here? What is it all about if it not for this?

There may be marginal growth in one particular year, but basically if this imbalance is to be remedied, can there be any such substantial growth in exports unless some basic policies, not only of us, but of those advanced countries, those developed countries with whom we have to deal are also changed?

This Report has admitted that the only countries with which there is not an unfavourable trade balance, but favourable trade surplus, in our favour are the countries of socialist communities, Eastern Europe and the Soviet Union and to a much lesser extent Africa. It is admitted here. But in the other countries, particularly the Western advanced countries there is a recession going on. And it is there where you are trying to sell your exports.

Then there are the fluctuating exchange rates. This is admitted here. And above all there is a fact that those countries are very consciously and planfully practising various types of protectionist measures both fiscal as well as non-fiscal to prevent exports from the developing countries coming into their markets on any substantial scale. That is mentioned in your Report itself So, are you in a position to change those things?

You may be able to show in a particular year two per cent or four per cent increase in export that has taken place. That is a different matter. It may be due to combination of various circumstances. But my point is we have to judge the new Import Policy declared the other day against this background and then say what do we find.

This new policy which has been declared should in my opinion have put much more emphasis on the question of import substitution i.e. the question of self-reliance, import substitution which was one of the goals which our Planners had put before themselves long ago. Instead of that, the new policy is a policy of what they call 'Import Liberalisation'—just the opposite. And what is that Import Liberalisation? About 100 items of raw materials and components have now been brought under the Open General Licence in this policy: 85 items of machinery have been brought under the OGL and those export units which are referred to as 100 percent export units, are supposed to export their entire production abroad, have been given 100 per cent

[Shri Indrajit Gupta]

freedom to import, as much as they want, whatever they want. And then Sir, a very strange thing has also happened. Up to now the prevailing Import policy at least did not allow import licences to those who are considered to be non-users: only to the actual users, the person who actually uses those items for production was to be given a licence. But under the new policy even the non-users are to be given licences. That means that they can import this material even though they are not the producers themselves; and then they can sell it here in the market naturally at black-mail rates. This is a new thing that has been introduced.

And then there is a free import of foreign technology and know-how. All these years we have been repeatedly assured in this House that only that foreign technology and that technical knowhow will be allowed to be imported, which we do not have in this country at all and which is very urgently required; and such foreign technology import will not be permitted which impinges upon our indigenous technology, which prevents our indigenous technology from being developed. Also, I should say that in any developing country—and India is not an exception to that—there are to many industries here, our own domestic industries which are still, I should say nascent industries. They have not fully developed or fully grown. And in such countries they have to be given some protection. They have to be given some protection because otherwise the gates will be open for competition from people who are hundred times more powerful with tremendous resources and technology at their disposal. But now this free import of foreign technology and know-how which is outlined in this Import Policy, I don't know whether the Minister will admit that is something basically and radically new is sought to be introduced now. The Open Door policy for foreign capital is now being replaced by open door policy for foreign goods and foreign technology. I know the answer that will be given because the officials of the Commerce Ministry are not at all reticent. They have been speaking freely very well and loudly about it, trying to advertise this policy as being some thing which will produce a miracle in our exports absolutely. We will be able to get all sorts of wonderful technology and all that. It will boost up our exports like anything. This is the sunshine story spread out by the Secretary of the Commerce Ministry and the other gentleman whose statements we read in the Press. But we should know that these foreign advanced countries hardly give their best or the latest or most efficient technology to countries like ours. It is well-known and everybody knows that. Anybody who knows about economics knows it. It is always the substandard and obsolete technology that is passed on to poor developing countries. So, no country can show whereby simply by importing technology from abroad, they have been able to stimulate their exports on a very substantial scale. And it will not happen in the case of India too.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): It happened in other country also.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Yes, they have purchased the technology outright. There is a different process they followed in Japan.

I should say now this that the Minister wants to worship at the alter of the IMF with a vengiance. We have been quoting here day after day from the documents and memoranda of the IMF itself. And one of the main prescriptions they had given at the time of the Extended Facility, which we were given was that import liberalisation on a big scale must be put through. These, so-called, adjustments must be made. Without that adjustment that Loan is not going to be given. But for myself, I did not expect that this capitulation would take place so soon and on such a big scale. The IMF Memorandum which was quoted so many times in the House earlier on had confidently forecast that the Indian trade deficit will rise to its peak in 1983-84, not now. That means even if exports go up a little bit, imports will go up much more because that is the policy that you are adopting -requiring "substantial additional borrowing much of it on commercial terms". This is what IMF has forecast; and that is the path on which you are going; i.e. after the period of IMF loan is over,

they themselves have said that you will have to go in for commercial borrowing on a big scale which means at what rates of interest you know very well.

I would like to draw the attention of the Minister to the 23rd Report of our own Estimates Committee, which has been submitted only recently. I am afraid the Reports of these Committees of the House are nowadays given very very low priority in the matter of consideration by Parliament. We never discuss a single one of our reports. They are printed, published and put away in the libraries. I do not know how many of these reports are seriously considered; but they are never discussed at least.

This 23rd Report of the Estimates Committee has a very interesting thing to say about the pattern of trade deficit because one thing which is always being said by my hon. friend Mr. Shivraj Patil is that this constantly rising value of imports is almost entirely due to the prices of petroleum and petroleum products. I do not deny that prices of POL have been going up frequently. It is a world-wide phenomenon. But the impression created is that but for POL, if we remove them from the export-import balance sheet, then you will find that things are not so bad, and that our exports are doing much better than our imports. It is not a fact.

The Estimates Committee's 23rd Report has given enough facts and figures to show that even without POL, the other non-POL imports are every year exceeding our exports substantially, by Rs. 300 crores, Rs. 400 crores or Rs. 500 crores. They have said that so long as this situation continues, the import of non-essential items should be very strictly controlled. But under the new import policy announced now, I am afraid even a large category of non-essential items will be permitted free entry.

The Estimates Committee has also pointed out that the unit value of many of the items which we export, i.e. what we realize, is much less in many cases than the unit value of the same items which are exported by other developing countries. They realize a higher item value than we realize and they have pointed this out—these are not my findings, viz. that this feature is due to the fact that in our country, there is a very large scale theft of foreign exchange going on by means of under-invoicing. Large scale under-invoicing by our businessmen is leading to this loss in foreign exchange; and the unit value of our export items is on the low side.

PROF. N. G. RANGA : It is for a long time that this is going on. Something has to be done.

SHRI INDRAJIT GUPTA: So, far as this import policy is concerned, our worst apprehensions are coming true; and I am afraid this is going to really have a crippling effect on many of our own domestic industries. The Indian machine-building industry has been struggling to get along—it has some achievements to its credit, I should say also; and the Indian machine-building to-day is in a position to supply first class equipment to many of our industries, whether they are textile, engineering or even heavy electrical equipments etc—but if you open the flood gates like this to the entry of foreign goods including machinery—because our Indian businessmen and Indian industrialists, especially those who belong to the large industrial houses have developed a mentality that they will always import foreign machines rather than have Indian ones—this is going to have a deleterious effect on the Indian machine building industry also, which requires some kind of a protection, some amount of encouragement and some amount of protection from getting crushed out of existence by these powerful foreign multinationals, with which they cannot compete.

So, the main thing I wanted to say is that this policy is absolutely an anti-national policy, against the interests of our nation, and that this policy should be opposed and fought tooth and nail. No support can be given to such a policy which is reversing the whole goal of

[Shri Indrajit Gupta]

national self-reliance and import substitution and independent economic development which we are supposed to be pursuing all these years, and without which no industry can stand.

I will raise 1 or 2 points before concluding, since my time is running out. They are both connected with the textile industry to which the previous speaker referred, but first I would refer to the jute textile industry. It is said here in this regard that the jute industry is facing a very serious recession due to decline in export demand; and, therefore, exports are declining and that there is recession and all that kind of thing. It is true to some extent, I admit, because the industry has been developed in such a way that it is critically dependent on foreign markets. It has always developed in such a way that other alternative uses, diversified uses of jute goods have not been developed or seriously pursued by these mill owners; and they have depended overwhelmingly on the export market, which previously used to be for hessian and after that, for carpet backing. And if for any reason, the demand declined in US or other overseas markets, immediately we are told that there is a terrific crisis in that industry.

Even then, according to his own report, the jute industry is still one of our major foreign exchange earners. Inpite of these recessionary conditions, the figures here show that in 1979-80 the foreign exchange earned by the jute industry was Rs. 334 crores, whereas in 1980-81 it came down to Rs. 326 crores. It means that only Rs. 8 crores of export earnings went down. But it is certainly a valuable and crucial industry for our purpose. In this year, which has been declared as the Year of productivity, it is a deplorable fact that at this moment in West Bengal, about 14 jute mills are lying closed, not because of strike by workers, but because of lock-out or something else by employers; and so much of production capacity is completely crippled and paralyzed. I do not know what steps Government is proposing to take to get these mills into operation again.

At the same time, in this last season, which has just passed of raw jute cultivation, it is again admitted in the report that during the past season, prices the growers of raw jute obtained were generally lower than even the minimum support price which the Government of India proclaimed at Rs. 175|- per quintal. Even that price the raw jute growers did not get. And mills are lying closed. This report does not help us to understand at all what needs to be done, what is the remedy and what the lines on which this industry should be tackled.

There is a mention here of a Task Force set up for the jute industry by the Government. I know some of its members. That Task Force has submitted as early as in February 1981 its report which consists of about 8 or 9 very important recommendations, as to how to rehabilitate this industry, and put it on its feet. Very valuable recommendations are there, I should say. I am not able to go into them, for lack of time; but the main thrust of these recommendations is that the industry should acquire a new look. It should do some market research; it should look for alternative uses for jute products, and should do modernization from that point of view. At the same time it should try to see that the cultivators get decent price for the fibre. But this report does not tell anything about what is the fate of the Task Force report. All it says is that the report was again referred to some committee of the officials or something. There the matter rests; and nobody knows if those recommendations are going to be buried for ever or what is going to happen. So, this is the very sad plight that the jute industry has come to. I would request the hon. Minister to give some serious thought to it. During the last year, they went out of their way to give the mill owners many benefits and concessions hoping that would stimulate them to revive the industry; they gave them some Rs. 70 crores additional credit for buying raw-jute, because they said, they did not have any cash. Even after that nothing happens; nobody knows where those Rs. 70 crores went also.

And export subsidy was increased from the 1st of September 1981. Still nothing happens. So, either this industry under its present owners has got to be radically restructured; if that cannot be done, this industry has to be taken over. It is one of our principal foreign exchange earners, giving you nearly Rs. 400 crores every year. It cannot be allowed to be ruined and destroyed like this by a hand-ful of big jute mill owners.

Last few points about the cotton textile industry, of course, much is being said here by other members also. Here I also regret to say, at this moment, in this year of productivity, the fact of the matter is that entire textile industry in Bombay is closed. You may blame anybody you like. You are the Government running the show. 64 textile mills in Bombay, the State from which the hon. Minister himself comes, 64 textile mills employing 2.5 lakh workers are closed since the 18th of January. I do not know how much production is involved; but this I do know that because of some question of prestige that they will deal with only such and such a union; we will not deal with anybody else; and the union with whom they want to deal is completely isolated from the workers; the workers do not follow that union. They are out on strike. All they want is that their representatives should also be called for some negotiations to settle the strike; but nothing is happening; and this strike is dragging on.

13.58 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

It is one of the biggest textile strikes that Bombay has ever seen. It is not a very good thing to the credit of the Government. At the other end of the country, in my own State, I would remind the hon. Minister that the largest mill, cotton textile mill, composite mill in Eastern India, that is the Birla Keshoram Cotton Mill in Calcutta, employing 10,000 workers had been locked out by the management since the 6th of December and this is April now. Production of this Birla Keshoram Cotton Mill comes to 2.80 lakh meters of cloth per day; just calculate the loss. And the net profit this Keshoram Cotton Mill has been making is like this. Is it running at a loss that it had to be locked out ? In 1978-79, its net profit was Rs. 3.46 crores; in 1979-80, its net profit was Rs. 5.10 crores and in 1980-81, its net profit was Rs. 5.66 crores. This company out of which the Birlas are earning so much profit, that has close down its largest unit employing 10,000 workers from the 6th of December; and now we are on the 12th of April and nothing is being done. My complaint is that nothing is being done, whatsoever to get these employers to reopen the mill and run it. If the workers go on strike somewhere, we are told that they are doing something terrible anti-social and the whole country will be destroyed by the irresponsibility of the workers and all that. But where these employers, powerful employers are involved, closing down their production units, the Ministers of our Government have no courage to say boo to the goose; maybe for other considerations I do not know what; because this is the election season again now unfortunately.

14 hrs.

The last point I want to make is— I would request him to look into it that is why I am raising it here—regarding his own National Textile Corporation. I know the entire National Textile Corporation in the country is in difficulty and is showing very poor results. There is no doubt about it.

And one of the main reasons for it no doubt is the fact that under the pressure of the private textile mill owners the Government agreed that they would have no further responsibility for manufacturing, what is called the controlled cloth, or cheap cloth, the cloth which is required by the vast rural masses of our country. That was taken away from them and the whole responsibility was put on the NTC. Everybody knows that you cannot make much of a profit out of the cheap cloth, controlled cloth; it is not meant to make profit out of it also. All

[Shri Indrajit Gupta]

the profit making varieties of cloth, fine, super-fine and everything is left to the private mill owners and the NTC mills are burdened entirely with the burden of producing this cheap and controlled cloth That I suppose, is the basic reason why the balance sheets of the NTC mills do not show profits. But anyway, I am referring now particularly to the Eastern Region subsidiary of the NTC comprising about 14 mills in West Bengal alone. In one year, 1980-81 the net loss of this subsidiary, as published in their own balance sheet, the Seventh Annual Report is 10.88 crores—their net loss! There is an Auditors' Report included in this Annual Report and it says in one place, if I may quote, this is what the Auditors have said:

> "We were given to understand that the Corporation has an internal audit system. In our opinion, such system is not commensurate with the size of the Corporation or any of its business. It requires to be adequately enlarged and extended to various areas of its activities."

Now, the Chairman and the Managing Director of this subsidiary, of the Eastern Region, Mr. S. K. Bannerjee, who has been in control since 1978-79, has been accused of making various inconsistent and contradictory statements. He appeared before a Parliamentary Committee also last year, headed by Mr. R. R. Morarka which went to Calcutta, specially to study the affairs of this NTC and all sorts of inconsistent and contradictory statements were made by the Chairman and Managing Director and if one tries to sort out those contradictions .... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: What is the name of the Committee?

SHRI INDRAJIT GUPTA: A Committee of the Parliament.

MR. CHAIRMAN: What Committee?

SHRI INDRAJIT GUPTA: It must have been the sub-committee of the Public Accounts Committee of the Public Undertakings Committee. It is therefore suspected that the bulk, for example the bulk of the yarn being produced by these mills, in the Eastern region is not being sold, as it was meant to be sold by a Government agency to the handloom sector and Government cooperatives and all that, but is being sold to private agencies.

There was a case in the Calcutta High Court involving this Eastern Region subsidiary of NTC. Case No. 220 of 1980. That is some other matter I am not concerned with it at the moment. In delivering the judgment in this case on the 17th February 1981 Mr. Justice S. K. Roy Choudhury of the Calcutta High Court made a few comments and I would just like to quote one or two of them, because they are of a general type of comments:

> "The whole object and purpose of the provisions in the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder is to see whether the business is carried on, following the commercial norms and honestly and in a regular manner. There is no dispute that the respondent company—meaning this NTC—has taken over the sick textile units to bring them to line by an efficient and honest management. But I can take a judicial notice of the notorious fact that it has utterly failed to do so. On the other hand, the attitude of the present management of the respondent—company is such that it gives the impression to the Court that they are not bound by the laws of the land or by any provisions of the Companies Act, 1956 and whatever they say must be accepted as gospel truth both in fact and in law. The high and mighty attitude on the part of the respondent Company is really sickening and I do not think that the Court should take by any notice of any fact or law which has no basis and particularly the Court will not rely on technicalities. However, the respondent-Company, being a Government company, and a top heavy administration which is managing the sick units, and whether they have brought back health to the sick units or not is a question to be enquired into elsewhere."

That did not come within the ambit of that particular case.

What I am saying is that there is something very seriously wrong with the eastern region unit of the NTC. For example, you will find from the Annual Report they have spent a substantial amount, invested about Rs. 35.91 crores on modernisation of machinery. But, along with the modernisation of machinery, one finds that the machine utilisation is going down all the time. Somebody has to look into it. How can this happen?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That process is on.

SHRI INDRAJIT GUPTA: My information is that in this process of modernisation, the Technical Director and some other technical experts who are there are being ignored in favour of setting up, what he calls,—this is mentioned in his Report— the Modernisation Committee, consisting of senior executives. They may be senior, or may be anything, but in this particular matter, the Technical Director and the technical experts have to be given priority; otherwise, it becomes highly irregular;

There are also certain serious charges, which I do not want to lay here because I cannot prove them; I do not know whether they are correct or not but they have appeared in the press—charges of malpractices in the negotiations for the purchase of this new machinery. It should be looked into.

Finally I would like to ask one question. Of course I do not know whether he is in a position to reply. I am told that the affairs of the eastern regional subsidiary have reached such a stage that there was an internal inquiry and audit by the Ministry—perhaps by his predecessor, I do not know. It was carried out by one genetleman, who is in charge of the holding company of NTC and the Secreary of the Department of Textiles perhaps. They carried out an internal inquiry and they have submitted a report, I am sure. Whether that report justifies that at least this Managing Director, Shri Banerjee, should be removed immediately, if this subsidiary is to be saved or rescued in any way. It cannot be done by keeping in office this gentleman, who has practically led it to its liquidation. If there is such a report, and if there is such a recommendation, however confidential it may be, I would very much like to know....

MR. CHAIRMAN: Now it is no more confidential.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Neither the previous Minister, nor the present Minister seems to be inplementing it or taking any action on it.

I only wanted to refer to one or two matters. There are so many things covered by this Ministry's activities that one is tempted to speak about many more things.

MR. CHAIRMAN: I think you have given them enough of food for thought and action.

SHRI INDRAJIT GUPTA: For thought? I thought it is meant for digestion. But, it cannot be digested.

I do not wish to take up more time. I thank you for the indulgence given to me. But, of course, my main quarrel is with their basic policy, the new import policy by which, I think, he is going to bring grief and disaster to our economic development.

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Mr. Chairman, Sir, on the Demands for the Grants of the Ministry of Commerce, I rise to say a few words on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam.

The new import-export policy which has been announced recently has to be welcomed because it is in consonance

*The original speech was delieved in Tamil.

(Shri Era Mohan)

with the avowed objective of accelerating production in 1982 and the Government have announced 1982 as the Year of Productivity. In this new policy of imports and exports, many concessions have been given for the import of plant and machinery which will in turn increase the pace of production. It is needless to reiterate that we have to earn more and more of foreign exchange through augmenting our exports in order to ensure rapid economic growth.

It is really unfortunate that after the announcement of 1982 as the Year of Productivity the Government of India have declared the policy of credit squeeze, in consequence of which the commercial banks and the nationalised banks refuse to give overdrafts and loans to businessmen and traders. Here it is necessary to make an exception for the export traders. The commercial banks and the nationalised banks should be directed to exempt the export traders from the credit squeeze policy and extend all the necessary monetary facilities to them in national interest. The hon. Minister of Commerce should exercise his good offices in this matter so that our export trade is not handicapped for want of finances.

I have to point out here that in 1981 the imports from England were 100 per cent higher than our exports to England. Naturally there has been a severe adverse balance of trade so far as our trade relations with England are concerned.

This calls for immediate scrutiny by our Commerce Minister and steps are to be taken to set right this unhappy situation. This assumes an alarming situation if the trade with rupee-payment countries is very much on the high side. Our trade with non-rupee payment countries, known as hard currency countries, has been declining steadily. This has inevitably affected our foreign exchange reserves. The value relation of rouble and rupee is low, while the value relation of dollar and rupee and pound and rupee is really high. We should endeavour effectively to set right this imbalance and improve our trade with hard currency countries.

Presentliy, rice has become the major foreign exchange earner. While the Basumati rice is in great demand in foreign countries, we are exporting more of IR 106, Parimal rice. While the Basumati rice can fetch outside Rs. 6000 per tonne, the price outside for parimal rice is just about Rs. 3400 per tonne. Inspite of this substantial price difference, we are exporting more of Parimal rice. Our efforts should be to export more of Basumati rice so that we earn enormous foreign exchange. Parimal rice should be kept for internal consumption and all the Basumati rice should be reserved for export.

Recently we have entered into an Agreement with the USSR for the supply of 1.75 lakh tonnes of rice. The Food Corporation of India has been entrusted with this gigantic export effort. In the background of heavy pilferage taking place in the F.C.I. which is worth several lakhs of rupees,— this is surely the sign of mismanagement—I doubt very much whether the F.C.I. will be able to meet its obligations, The F.C.I. has also no expertise in exports. I am apprehensive of our country's name being sullied in the USSR. It may have an adverse effect on future trade relations also, with the U.S.S.R. I feel that we should not hesitate to utilise the services of Export Houses in the private sector who have experienced personnel to tackle such tasks. We may impose strict restrictions on their activities. I am suggesting just to ensure that we honour our commitment of supplies as per the schedule of the agreement. The Commerce Minister has a vital role to play in this matter. We can give some quantity to these private sector export organisations and the balance can be exported by the State organisation.

I am constrained to say this because of the failure of State sponsored export organisations like NAFFD. NAFFD was entrusted with the task of exporting

onions. This apex export body could not do the job and the export of onions had to be farmed out among private sector export organisations. The export of onion was de-canalised except in the case of Malaysia. Even in the case of Malaysia, NAFED could export only 35 per cent and the remaining 65 per cent export was done by a private sector export house. Because of the prevailing confusion, there is demand for decanalisation of onions even in the case of Malaysia. The growers of onions have become the victim because they are not getting remunerative prices. In other countries, the exports are primarily done by expert organisations. At this juncture, we are mainly concerned with earning more foreign exchange by expanding our export programme and for that we need not stick to slogan of state sector and private sector. We should utilise the services of such export organisations in the private sector coupled with the authority bestowed on the State-sponsored export agencies.

In the country's total export of handloom fabrics, Tamil Nadu occupies premier place. Lakhs and lakhs of people in Tamil Nadu depend upon handloom industry for their livelihood. The Tamil Nadu handloom fabrics used to occupy pride of place in the international markets. But today, stocks of handloom fabrics worth hundreds of crores are stagnating in Tamil Nadu. Every week exhibitions of handloom fabrics are held just to promote the sale of handloom cloth. Yet the Government of India has not taken keen interest in promoting the export of handloom cloth in foreign markets. It should be given the top priority of the Government of India to boost the export of handloom cloth to foreign countries. If this is not done, lakhs and lakhs of handloom weavers in Tamil Nadu will face strarvation deaths. Whatever fillip is required for this purpose, the Centre should not hesitate to render.

Till recently India held the sway in international market for its turmeric. 85 per cent of world's requirement of turmeric was met by India. Out of this 65 per cent came from Tamil Nadu. Because of our negligence, China has captured the world market for turmeric. It may be due to the lower price of Chinese turmeric that we have lost the international market. I demand that immediate attention should be paid to the export of turmeric and we should restore to ourselves the lost market.

We have Free Trade Zones in Kandla, in Santa Cruz in Bombay and in several other places for improving our export performance. The Free Trade Zone for Electronic products in Santa Cruz has become a remarkable success. During the past two years, whenever I got an opportunity to speak on this subject, I have been repeatedly stating that a Free Trade Zone should be set up in Meenambakkam Airport Zone in Madras for electronic goods. In Tamil Nadu we have eminent men in electronics and we have also entrepreneurs ready to invest all the money required for this purpose. So far there is not a single Free Trade zone in Tamil Nadu. By setting up this Free Trade zone near Meenambakkam, Tamil Nadu will get the justice done to it. Similarly, Coimbatore is known as the Manchester of India with 105 textile mills and hundreds and thousands of Steel Foundries. There is substantial production of handloom fabrics also here. Adjacent to Coimbatore is Tiruppur which is known for its hosiery throughout the world. From Nilgiris and Anamalai, which are on the outskirts of Coimbatore, tea is exported. If a Free Trade Zone is set up in Coimbatore, then Coimbatore will be on the world map That will give the much-needed boost to exports from Coimbatore. That will also create the necessary indusrial infrastructure in and around Coimbatore, which is suitable for export markets. I demand that a Free Trade zone on the pattern of Kandla or Santa Cruz Free Trade Zone should be set up in Coimbatore.

India is peninuslar in its real sense with long coastline on three sides. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh have the longest coastline as compared to many countries of the

[Shri Era Mohan]

world. In our exclusive economic zone, we have abundant marine wealth which remains unexploited so far. Even smaller countries are exporting more of marine wealth than India. Our fishermen are using the age-old catamarans. They have no mechanised boats capable of going deep sea for catching more sea food. It is really unfortunate that we have not laid emphasis on the export of marine wealth so far. By exporting marine wealth alone, we will be able to get maximum foreign exchange earnings. Yet we have neglected this area of great potential for exploiting to the country's good. The Commerce Minister should devote his attention to this field and ensure that our foreign exchange reserves are built on the export of marine wealth alone.

I do not understand the reasons for banning the export of sandalwood. For the past two years I have been referring to this on the floor of this House. In reply to a question raised by me some fifteen days ago, I was told that Tamil Nadu could send the Sandalwood to Karnataka, as if Tamil Nadu can earn foreign exchange by selling it to Karanataka. I cannot understand the logic of this reply. When crores worth of sandalwood are lying moth-eaten in Tamil Nadu, when the blackmarketeers smuggle out cut-pieces of sandalwood, why should there be ban on the export of sandalwood from Tamil Nadu? I demand that the ban on the export of sandalwood should be lifted immediately. There is no need for it at all. When we are in need of foreign exchange, we should allow the export of sandalwood.

Before I conclude I would refer to another sordid feature of the working of this Ministry. In Coimbatore 13 sick Textile Mills were taken over by the Tamil Nadu Textiles Corporation when my party the D.M.K. was in the Government. Earnest efforts were made to bring them back to life. Suddenly, all these 13 sick textile mills were taken over by the National Textiles Corporation working under the jurisdiction of the Ministry of Commerce. Besides these 13 sick textile mills, one sick textile mill in Pandicherry has also been taken over by the N.T.C. While these were in the charge of private management, the retired workers, the retired Government employees and teachers had invested their savings in these Mills as fixed deposits. Deposits of Rs. 5,000 or Rs. 10,000 by such people had swelled the coffers of these mills at that time. Now I understand that though these deposits have matured, the NTC is not paying them back to these small investors. Some widows have come and complained to me, after bemoaning and bewailing their financial lot. If the NTC does not return the deposits of affluent people I cannot have any complaints. But it is really cruel not to return the deposits of retired workers, widows, retired government employees and teachers. The Government of India should direct the NTC to return the deposits of these people immediately.

I am sure that within the framework of the new import-export policy we will be able to have a favourable balance of trade with substantial foreign exchange earnings to our credit.

With these words I conclude.

श्रीमती कृष्णा साहो (बेगूसराय) : सभापति महोदय, नई आयात निर्यात नीति में उत्पादन बढाने तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये आयात लाइसेंस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। मंत्री जी ने नई आयात नीति की घोषणा करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि नई नीति के फलस्वरूप तकनीकी प्रगति के साथ साथ देश को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। विदेशों में बसे भारतीयों से पूंजी आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाये गये है। साइंस और टेक्नोलाजी के सामान का उत्पादन करने के लिये भारत में जो उद्योग लगाना चाहते है,उन्हे भी काफी रियायतें एवं सहूलियतें दी जायेंगी। लघु एवं कुटीर उद्योग की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार की जो ये सारी नीतियां

है, उन का मैं स्वागत करती हूं । ये रचनात्मक नीतियां है और मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं और साथ ही साथ मंत्री महोदय का ध्यान अभ्रक उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं ।

आप भी जानते हैं और यह सारा सदन जानता है कि सारे देश में जितना अभ्रक का उत्पादन होता है, उस का 70 प्रतिशत बिहार में उत्पादन होता है। यह अभ्रक झुमरी तलैया और कोडरमा के इलाके का होता है । कुछ वर्षों से अभ्रक उद्योग में अभूतपूर्व मंदी आ गई है और छोटे और मध्यम श्रेणी में अभ्रक के उद्योग धंधे में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि आज के वैज्ञानिक युग में अभ्रक उद्योग की ओर विदेश के लोगों की आंखें लगी हुई हैं, हम उनकी ओर से उदासीन हो कर बैठे हैं ।

सभापति महोदय : और हम लोगों ने आंखें मूद ली हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : जी, हां। मेरा कहना यह है कि इस उद्योग की क्रय नीति, उत्पादन और विकास की नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है और उस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । सन् 1978 में बिहार सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था और उस में उन्होंने ऐसी अनुशंसा की थी कि जिस प्रकार से चाय और काफी के बोर्ड हैं उसी प्रकार से एक अभ्रक बोर्ड की स्थापना भी की जाये क्योंकि भारत में खानों से निकाले गये अभ्रक का 90 प्रतिशत भाग कच्चे पदार्थ के रूप में निर्यात किया जाता है। इसलिये अभ्रक उद्योग का यदि आधुनिकीकरण नहीं किया गया और उस का विकास नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी, अपार राष्ट्रीय क्षति होने की संभावना है, बल्कि हो रही है ; अभ्रक का निर्यात पूर्णतया भारत सरकार के प्रतिष्ठान अभ्रक व्यापार निगम द्वारा ही किया जाता है और यह भारत सरकार का व्यापार निगम है, यह बड़े बड़े व्यवसायियों से, व्यापारियों से अभ्रक खरीदता है जबकि जो छोटे व्यापारी है या जो माध्यम श्रेणी के व्यापारी है, उन से भी उस को यह खरीद करनी चाहिये थी ताकि उन का शोषण न हो सके लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ।

इस के साथ ही साथ सब से खेद की बात तो यह है कि अभ्रक की खानों की गहराई बहुत नीचे चली गई है, जिससे निजी व्यापारी अपनी धनराशि लगा कर उसे दुरस्त नहीं कर सकते हैं । इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि वैसे छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाय, उन को ऋण देने की व्यवस्था की जाये ताकि अच्छे अभ्रक खानें बरबाद होने से बचाये जा सके और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है । जहां एक ओर हम पेट्रोलियम पदार्थों और अनेक ऐसी चीजों पर विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं, वहां हम यदि ऐसे उद्योगों की ओर भी ध्यान दे तो हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी और हमारा आर्थिक क्षेत्र भी प्रगति करेगा ।

बिहार के सिंहभूम में लौह अयस्क होता है। उसके उत्पादन में निरन्तर ह्रास हो रहा है। यह सही है कि सिंहभूम में जो लौह अयस्क पैदा होता है उसमें गुणत्मकता की कमी है । उसमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी कि होनी चाहिये । फिर भी जो हमारी एम० एम० टी० सी०

[श्रीमती कृष्णा साही]

जैसे संस्थान है वे इस लौह अयस्क को ब्लेंड कर देश के अन्दर इसकी खपत को बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे ग्रेड के साथ मिला कर इसका निर्यात भी कर सकते है। आज बिहार में ये खानें बंद होने के कगार पर है। अगर ये बंद हो गयी तो लाखों श्रमिकों को अपनी रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ेगा और साथ ही साथ कानून और व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जायगी ।

सभापति जी, आप जानते है कि बिहार में भागलपुर में तसर और मूंगा सिल्क का उत्पादन होता है। विश्वभर में उसका नाम है। हम जब विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां की बाजारों में इसकी बड़ी मांग है। इस प्रकार हम इसके निर्यात को बढ़ा कर भी लाखों लाखों रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक युग में जहां गुणात्मकता की होड़ लगी हुई है उसमें हम अपनी पुरानी टेक्नोलोजी के सहारे कब तक प्रतिद्वन्द्विता में ठहर पायेंगे। हमें चाहिये कि हम वैज्ञानिक ढंग से इसकी गुणात्मकता को बढ़ाएं और इस उद्योग की प्रगति करें। जहां हमारे इतने अधिक संसाधन हैं, वहां हम इस उद्योग की प्रगति चतुर्दिक विकास कर के भी अपने संसाधन बढ़ा सकते है, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सकते हैं ।

मैं वस्त्र निर्यात के बारे में कहना चाहती हूं कि वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में भारत की गणना संसार के सर्वाधिक वस्त्र निर्यात करने वाले देशों में होती है। केवल परिमाण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि श्रेष्ठता की दृष्टि से भी भारत बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्रों का निर्यात करता है। भारत के वस्त्र निर्माता तो अत्यधिक विकसित टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हैं। हमारी यह एक बुनियादी और पुरातन इंडस्ट्री है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था इस इस उद्योग पर बहुत निर्भर करती है। बोम्बे जैसे प्रांतों की तो यह इंडस्ट्री बेकबोन है ।

लेकिन आज इस उद्योग में क्या हो रहा है ? 1981 के सितम्बर तक इस उद्योग में 22 काटन मिलें बंद थीं। फिर जनवरी से बम्बई में ही 60 काटन मिश बंद हुए जिसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ रहा है। जैसे केमिकल्स डाई, हार्डवयर, पिगमेंट आदि उद्योग तो प्रायः समाप्त हो रहे हैं। हजारों लीटर दूध जो इन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था वह भी बर्बाद हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिय और अनुशासन भंग करने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिय।

सभापति महोदय, इसके साथ ही में कहना चाहती हूं कि 1968 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना हुई थी । 1972–73 में इसने 103 बीमार मिलों को अधिगृहीत किया। 1981–82 में 112 मिलें इसके अधीन थीं। यह निगम 1974–75 से घाटे का सामना कर कर रहा है। दिनों दिन यह अस्वस्थ होता जा रहा है।

सभापति महोदय : इलाज भी हो रहा है या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, यह तो इतना अधिक अस्वस्थ हो गया कि खाट पकड़ ली है। अब तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि यह बिल्कुल ला इलाज हो रहा है। हमने इसके बारे में देखा है कि 1978–79 में इसमें सवा दो अरब का घाटा था तो 1981–82 में ढाई अरब का घाटा हुआ। इस संबंध में उप मंत्री का वक्तव्य भी देखा। 1980–81 में निगम के अधिकारियों ने

यह दावा किया था कि इसमें 6 करोड़ रुपये का लाभ होगा और अब हम घाटे की घाटी से निकल चुके है। जो निगम 6 करोड़ का नफा देने वाला था वह कहां तक यह दे सका इसको हम सब जानते हैं। आज के युग में गुणात्मक प्रतिद्वन्द्विता की होड़ लगी हुई है। इसलिए इसको आधार मानकर निगम ने कहा कि इसका आधुनिकीकरण होना चाहिये लेकिन आधुनिकीकरण तो नहीं हुआ। आधुनिकीकरण के लिए ढाई अरब रू० की योजना बनाई गई, लेकिन मशीनों को रीप्लेस करने के बजाए उन्हीं पुरानी मशीनों को रंग-रोगन करके नया रूप दे दिया गया और वे काम नहीं कर रही हैं। 50 करोड़ की मशीनें विदेशों से भी आई, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार की नीति है और सिद्धांत है कि गरीबों के लिये कंट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराया जाए और इसलिए कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया गया। इसीलिए 1981 में यह बात सामने आई कि इसका उत्पादन 45 करोड़ वर्गमीटर से बढ़ाकर 65 करोड़ वर्गमीटर किया जाएगा और नये वस्त्र नीति के अनुसार हथकर्घा उद्योग को भी प्रोत्साहन देंगे, लेकिन क्या हुआ ? आज हमारा बुनकर मुसीबत में है। सूत और रसायन, महंगे हो गये हैं, इससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी समय रहते यदि इस पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा तो लोग बड़ी परेशानी में पड़ जायेंगे और अर्थव्यवस्था जो नष्ट हो ही रही है, साथ ही साथ रोजी-रोटी का प्रश्न भी लोगों के सामने उठेगा।

इसी संदर्भ में मैं मुकामा और गया स्पिनिंग मिल के बारे में कहना चाहती हूं जो बिहार में है। मुकामा में तीन वर्ष पहले स्पिनिंग मिल में एक मशीन 50 लाख की लेकर रखी हुई है और तब से वह वैसी ही पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय: केन्द्रीय सरकार की है या राज्य सरकार की ?

श्रीमती कृष्णा साही: केन्द्र सरकार की है, तभी तो कह रही हूं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा टेकओवर किया गया था।

सभापति महोदय: वह भी बीमार थी ?

श्रीमती कृष्णा साही: वह मिल बीमार नहीं थी, यदि मंत्री महोदय जाकर देखेंगे तो उनकी तबीयत खुश हो जाएगी कि 6 साल तक जब मिल बंद थी और मैं वहां विधान सभा की सदस्य थी, उस समय उस मिल को 6 साल बाद खुलवाया गया...।

सभापति महोदय: मैं देख चुका हूं।

श्रीमती कृष्णा शाही: आपने तो देखा ही है। तो मजदूरों ने कितनी मेहनत से हिफाजत की और उसका एक पुर्जा भी खराब नहीं होने दिया। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि वे देखें कि 50 लाख की मशीन आई तो उसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है।

हम लोगों ने तय किया कि गरीबों को कपड़ा उपलब्ध होना चाहिये, लेकिन क्या हो रहा है। गरीबों के लिये कपड़ा बनाया जाता है, उनके लिये पूरा तामझाम किया जाता है, लेकिन उनको 15 प्रतिशत

[श्रीमती कृष्ण शाही]

भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता है और निगम के कंट्रोल का कपड़ा वस्त्र उत्पादकों को दे दिया जाता है और वह शहरी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी दुकानों में बेचा जाता है और यह सब की आंखों के सामने है। 50 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे है और गांवों में रहते है, उन्हें कपड़ा उपलब्ध नहीं होता, इसके बारे में पहले भी लोग कह चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने जिन घाटे वाली कपड़ा मिलों को अधिग्रहित किया है, उनको वह क्या चलायेगा जो स्वयं बीमार है, वह दूसरे को क्या संजीवनी दे सकता है। उसका क्या इलाज कर सकते हैं? इसलिये प्राथमिक जवाबदेही है, उसको पूर्ण करने में यह सक्षम नहीं है।

मैं कहना चाहती हूं कि जो अवेलेबिलिटी आफ फेब्रिक्स है वह बहुत नीचे चला गया है और एक्सपोर्ट आफ काटन यानफेब्रिक्स 31 करोड़ से घट कर 21.39 करोड़ रह गया है और 16.8 मीटर 1964–65 में पर केपिटा एविलेबिलिटी आफ फेब्रिक्स था जो 80–81 में 15.0 मीटर हो गया। कहते है कि आबादी बढ़ी है, लेकिन यह अजीब बात है कि एक तरफ तो कपड़े की शार्टेज आ रही है और दूसरी तरफ इनके भंडार में इतना कपड़ा हो गया है कि लोगों के लिये सिरदर्द हो गया है कि उसकी खपत कहां की जाए। विरोधाभास की तरह यह लगता है। अभी हमारे देश की स्थिति को आप देखें। कपड़े के एक्सपोर्ट की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। उस तरफ से बड़े व्यापारी ध्यान हटा रहे है। अच्छे ढंग का और आधुनिक ढंग का कपड़ा बना तो रहें है, मिलें बना तो रही हैं लेकिन उसको वे अपने देश में ही बेंचना चाहते है, विदेशों में भेजना नहीं चाहते। नतीजा यह है कि हमारे देश में छोटे छोटे व्यापारी जो कपड़ा बनाने के काम में लगेहुए हैं वे इनके कम्पीटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं। बड़े उद्योग वाले अगर बाहर कपड़ा भेजें तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की बचत ही नही होती बल्कि उस में बढ़ोतरी भी हो सकती है और साथ ही साथ छोटे उद्योग धंधे भी चालू रह सकते है। यही मुख्य विन्दु थे जिन की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहती हूं। मेरा क्षेत्र आधा मोकामा में पड़ता है जहां स्पिनिंग मिल है। आप देखें कि वहां क्या क्या विकास हो सकता है। यह बिहार प्रान्त की ही बात नहीं है बल्कि सारे देश की बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अशफ़ाक हुसैन (महाराजगंज): कामर्स मिनिस्ट्री या वजारते तजारत दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक का नाम है डिपार्टमेंट आफ कामर्स और दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट आफ टेक्सटाइल्ज। वक्त की कमी को देखते हुए मैं अपनी बात ज्यादातर डिपार्टमेंट आफ टैक्सटाइल के बारे में ही कहूंगा। कामर्स के बारे में थोड़ा सा इशारा जरूर करूंगा, आपकी मार्फत।

जो बजट मांगें रखी गई है उस में खास तौर से हैडलूम का जो मुकदमा है उसको अव्वाम के नुमाईन्दों की सबसे बड़ी अदालत में मैं रखना चाहता हूं। मेरी समझ के मुताबिक हैडलूम के साथ नाइंसाफी बरती गई है बावजूद इसके कि बार बार यह कहा जाता है काम मिनिस्ट्री की तरफ से या सरकार क

तरफ से कि उसका खास ध्येय, खास तात्लुक हैंडलूम की तरक्की करने का है। मौजूदा हकूमत बराबर यह दावा करती रही है कि हैंडलूम और दस्तकारी को बढ़ावा देना उसका खास मक्सद रहा है। जो बीस नुक्काती प्रोग्राम, बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था उस में भी हैंडलूम और घरेलू दस्तकारियों की तरक्की के काम का जिक्र किया गया था और जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है उस में भी कहा गया कि हैंडलूम का एक खास मुकाम होगा। लेकिन हुआ क्या है ? नए बीस सूत्री कार्यक्रम में पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के मुकाबले में कम अहमियत दी गई है । पहले बीस सूत्री कार्यक्रम में हैंडलूम के बारे में दो प्वाइंट खास तौर से थे लेकिन अब नए बीस सूत्री कार्यक्रम में आखिर में एक प्वाइंट को रस्मन, एक नुक्ते को रस्मन हिस्सा बना दिया गया है । रस्मन में इसलिये कहता हूं कि इसका सबूत इस साल का बजारते तजारत का बजट है। गुजश्ता साल के मुकाबले में इस साल बजट एस्टीमेट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से नम्बर 2 पर बजट एस्टीमेट्स में साफ तौर से कहा गया है :

"The Budget Estimates 1982-83 show a decrease of Rs. 80.12 crores compared to Revised Estimates of 1981-82;"

यानी इस साल हैंडलूम की मद में 80 करोड़ 12 लाख 39 हजार रू० रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स से कम कर दिया गया तो आप खुद देखेंगे मेरी बात सही है या मलत है हर मद की तफसील में तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना रु० नये 20 सूत्री कार्यक्रम के लाने के बाद ही यह पहला बजट है जिसमें हकूमत ने हैंडलूम और दस्तकारों के साथ अपनी हमदर्दी का सबूत दिया है इस 80 करोड़ रु० को कम कर के। जब यह इब्तदा है तो इंतहा क्या होगी आप खुद अंदाजा लगा लें और वह भी नए 20 सूत्री कार्यक्रम के ऐलान के बाद।

PROF. N. G. GANGA: Handloom exports are going up.

श्री अशफ़ाक हुसन : हैंडलूम की सनत को सूत और केमिकल के मुनासिब दाम पर फराहमी के लिये 1980 में ऐलान किया गया था नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जायगा। बजट में भी पैसा रखा गया, लेकिन 1980 के बाद 1981–82 और 1982–83 में अभी भी नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कारपोरेशन किस स्टेज पर है यह पता नहीं है। और उसकी तरक्की इस तरह से हो रही है कि साल की बजट मांगों में इस मद में पहले रखे गये 2 करोड़ रु0 की जगह इस साल उसे घटा कर 75 लाख 70 हजार रु0 कर दिया गया। तो कथनी और करनी में कितना फर्क है यह इससे साफ़ जाहिर होता है क्या 1 करोड़ 24 लाख 30 हजार रु0 की रकम कम करने का मतलब यह लगाया जाय कि हुकूमत इस कौरपोरेशन को वजूद में लाने में तेजी दिखा रही है या इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल रही है । हैंडलूम की फरोग के लिये सूती मिलों पर जिम्मेदारी डाली गयी कि बाजार में फरोख्त करने के लिये 50 फीसद सूत हैंडलूम के लिये तैयार करें और इस 50 फीसद सूत में से 85 फीसद सूत 40 नम्बर और उसके नीचे के नम्बर में तैयार होगा। लेकिन पोज़ीशन क्या है। 10 लाख 67 हजार किलोग्राम सूची धागे में से सिर्फ 2 लाख 60 हजार किलोग्राम हैंडलूम के लिये तैयार किया गया 1981–82 में। ऐसी पाबन्दी लगाने से क्या फायदा जिस पर अमल का जिम्मेदारी लेने के बाद भी अमल न होता हो ? यही वजह है कि नेशनल

[श्री अशफाक हुसैन]

हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन अभी तक वजूद में नहीं आया और इस साल उसके लिये रुपया भी कम कर दिया गया। हैंडलूम के मुनासिब दाम की फाराहमी के लिये जरूरी है कि 50 फीसद और 85 फ़ीसद की जो कानूनी पावन्दी 1978 में लगाई गई है उस पर सख्ती से अमल किया जाय। अगर आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं तो मिलों पर पाबन्दी लगानी होगी कि मुकररा मिकदार में सूत हैंडलम के लिय तैयार करें। और मेरा सुझाव है कि जब हम चीनी और सीमेंट की दोहरी नीति अपना सकते हैं तो हैंडलूम के धागे की फराहमी के लिये भी क्या दोहरी नीति नहीं, अपना सकते है। इस पर मंत्री जी विचार करें और साफ जवाव दें।

हैंडलूम के लिये दूसरी अहम जरुरत इसके लिये किए हुए दायरे पर सख्ती से अमल करना जरुरी है। क्षेत्र बना दिये गये कि हैंडलूम पावरलूम और मिलों पर यह कपड़ा बनेगा। लेकिन क्या उस पर अमल होता है। हो यह रहा है कि जो कपड़ा हैंडलूम पर बनना चाहिये वह खुले आम पावर लूम पर बन कर वाजार में आ रहा है, और पावर लूम पर बनने वाला कपड़ा मिलों के द्वारा बनाकर बेचा जा रहा है। किसी भी पाबन्दी पर कोई अमल नहीं हो रहा है। कागज़ पर हो तो हो। इन दोनों की दखलन्दाज़ी से महफूज़ रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें कोताही और ढिलाई हुकूमत बरत रही है। मौजूदा टेक्सटाइल पालिसी में यह ढिंढोरा पीटा गया है कि हैंडलूम को इज्जत का मुकाम दिया गया है। नायब वज़ीर साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहब का जो भाषण हुआ है, मैं तो तीन साल से भाषण सुनता आ रहा हूं कि हैंडलूम को इज्जत का मुकाम दिया गया है, लेकिन वह देखने में नहीं आ रहा है।

यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की कपड़े की सारी जरूरत हैंडलूम से पूरी की जायेगी। लेकिन कंट्रोल्ड कपड़े में, जनता साड़ी में हैंडलूम को सबसीडी 1 रुपये 50 पैसे फी स्क्वेयर मीटर दी जाती है, जबकि एन० टी० सी० मिलों को इस तरह की साड़ी के लिये 2 रुपये साड़ी दी जाती है। हैंडलूम का जो कपड़ा तैयार होता है, वह गरीब तैयार करते हैं और गरीबों के लिये तैयार करते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिये सबसीडी सिर्फ डेढ़ रुपया दी जाती है और एन० टी० सी० जब वहीं कपड़ा तैयार करता है तो धोती-साड़ी के लिये उसको 2 रुपये की सबसीडी दी जाती है। यह फर्क क्यों हैं, मुझे मालूम नहीं, मंत्री जी को इस बारे में बताना चाहिये।

यह इसलिये भी हो सकता है कि एन० टी० सी० मिलें सरकार की हैं और उनका घाटा नफा देखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और गरीब बुनकर जो देहात में रहता है, जिसका ताल्लुक कमज़ोर तबके से है, गरीब तबके से है, इसलिये उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। हैंडलूम के बुनकरों को अमली सबूत देना है तो आपको पहला काम यह करना चाहिये कि जो सबसीडी हैंडलूम को देते हैं वह एन० टी० सी० से बढ़ाकर दें। अगर एन० टी० सी० को 2 रुपये देते है तो हैंडलूम को ढाई रुपये दें। पिछले साल के मुकाबले हैंडलूम और एन० टी० सी० को दी जाने वाली सबसीडी की रकम कम कर दी गई है। सबसीडी कम करने का मतलव यह है कि हैंडलूम का कपड़ा भी कम तैयार होगा। जो कपड़ा जनता कपड़े के नाम से कहा जाता है, सबसे ज्यादा रकम इस मद में इस साल आपने कम कर दी है। आप तो लायक है, होनहार और नौजवान हैं और आपसे बहुत सी उमीदें वावस्ता हैं, इसलिये आपको खासतौर से समझना चाहिये कि इस

साल जो आपने रुपया सबसीडी की मद में दिया है, वह करीब 57.50 करोड़ पिछले साल के मुकाबले में कम कर दिया है। इस तरीके से करीबन 58 करोड़ रुपया कम करने से क्या हैंडलूम को बढ़ावा मिलेगा, क्या इस तरह से हैंडलूम की हमदर्दी का यही अमली काम है ?

1980–81 और 1981–82 के बजट में हैंडीक्राफ्ट के मद में 5 करोड़ 5 लाख रुपये कालीन ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर रखे गये जो कि इस साल बिल्कुल खत्म कर दिये गये। पता नहीं कहां इसको मर्ज कर दिया गया है ? हैंड निट कार्पेट जो देहात के गरीब बुनकर तैयार करते हैं, उनके ऊपर से सरकार की नजर कुछ फिर गई है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग के नाम पर जो रुपया मिलता था, उससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता था और इस हैंड निट कार्पेट से हम सीधे सीधे एक तरफ विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे और दूसरी तरफ देहात के बुनकरों को फायदा होता था।

हमारा मुल्क अपनी दस्तकारियों के लिये बहुत मशहूर है, चाहे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बर्तन हों, अलीगढ़ के ताले हों, सहारनपुर का लकड़ी का काम हो या काश्मीर का आइवरी का काम हो या ईस्ट में बांस का काम किया जाता है। इस साल के बजट में इन दस्तकारियों में जो आपने 10 करोड़ 49 लाख रुपया रखा है, यह इस बात का सबूत नहीं देता है कि आप दस्तकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये जरुरी है कि दस्तकारों और हैंडलूम के साथ जो अब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसमें आप कमी करें उसे खत्म करें। उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। चूंकि व कमजोर और पिछड़े हुए है, इस लिए उन्हें और प्रोत्साहन और प्रोटक्शन देनी चाहिए :

सभापति महोदय : मैं आपसे दरख्वास्त करूगा कि आप अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करें ।

श्री अशफाक हुसैन : मैं मांग करूंगा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की एक अलग से वज़ारत कायम की जाए

जो नई ऐक्सपोर्ट पालिसी घोषित की गई है, बहुत से साथियों ने उसपर कहा है और आपने भी कहा है कि वक्त कम है, इस लिए में श्री इन्द्रजीत गुप्त की तकरीर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहता ।

गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के सिलसिले में एक नया ऐलान अख़बारों में देखने को मिला है, जिसमें गारमेंट्स और फ़ेब्रिक्स के सभी तरह के कोटे को ख़ल्त-मल्त कर दिया गया है, एक में मिक्स कर दिया गया है। इससे हैंडलूम और फ़ेब्रिक्स का ख़सूसी कोटा ख़त्म हो गया है। इससे हैंडलूम और दस्तकारियों को नुकसान पहुंचेगा ।

ऐपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल के घपलों की तरफ़ इशारा करते हुए और उसके ओहदेदारों की बद-दियानती की तरफ़ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं कहुंगा कि उसके बारे में ख़सूसी तवज्जुह दी जाए ।

जहां तक जूट का ताल्लुक है, यह आपकी रियासत से ताल्लुक रखता है ।

सभापति महोदय : बंगाल और कुछ हद तक बिहार ।

श्री अशफ़ाक हुसैन : वहां पर दो जूट मिलें हैं । कटिहार जूट मिल को बदइन्तज़ामी की वजह से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और उम्मीद है कि अब वह सही रास्ते पर चलेगी । लेकिन जो दूसरी मिल वहां पर है, उसको कलकत्ता के कोई सेठ चमरिया चलाते हैं।

[श्री अशफाक हुसैन]

वह इस जूट मिल पर कम ध्यान देते हैं और कलकत्ता में अपने चमड़ा उद्योग पर ज्यादा ध्यान देते हैं । मज़दूरों की कई महीने की तन्ख्वाह और ग्रैचुइटी फंसी हुई है । उनका बोनस भी रुका हुआ है । डेढ़ करोड़ रुपये की रकम उन पर बाकी है । इस मिल को नैशनलाइज़ किया जाए, ताकि मज़दूरों को मज़दूरी मिले और जूट उद्योग की भी तरक्की हो ।

[شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

کامرس منسٹری یا وزارت تجارت دو حصوں میں بٹتی ہوئی ہے - ایک کا نام ہے ڈیپارٹمینٹ آف کامرس اور دوسرے کا نام ہے ڈیپارٹمینٹ آف ٹیکسٹائلز - وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات زیادہ تر ڈیپارٹمینٹ آف ٹیکسٹائل کے بارے میں ہی کہوں گا - کامرس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ ضرور کروں گا - آپکی معرفت -

جو بجٹ مانگیں رکھی گئی ہیں اس میں خاص طور سے ہینڈلوم کا جو مقدمہ ہے اس کو عوام کے نمائندوں کی سب سے بڑی عدالت میں میں رکھنا چاہتا ہوں - میری سمجھ کے مطابق ہینڈلوم کے ساتھ نا انصافی ہوتی گئی ہے باوجود اس کے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کامرس منسٹری کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کہ اس کا خاص دھیان خاص تعلق ہینڈلوم کی ترقی کرنے کا ہے - موجودہ حکومت برابر یہ دعوہ کرتی رہی ہے کہ ہینڈلوم اور دستکاری کو بڑھاوا دینا اس کا خاص مقصد رہا ہے - جو بوس نکلی پروگرام بوس سوتری کاریہ کرم بنایا گیا تھا اس میں بھی ہینڈلوم اور کھریلو دستکاریوں کی ترقی کے کام کا ذکر کیا گیا تھا اور جو نیا بوس سوتری کاریہ کرم بنایا گیا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ ہینڈلوم کا ایک خاص مقام ہو گا - لیکن ہوا کیا ہے - نئے بوس سوتری کاریہ کرم میں پہلے بوس سوتری کاریہ کرم کے مقابلے میں کم اہمیت دی گئی ہے - پہلے بوس سوتری کاریہ کرم میں ہینڈلوم کے بارے میں دو پوائنٹ خاص طور سے تھے لیکن اب نئے بوس سوتری کاریہ کرم میں آخر میں ایک پوائنٹ کو رسمی ایک نقطے کو رسمی حصہ بنا دیا گیا ہے - رسمی میں اس لئے کہتا ہوں کہ اس کا ثبوت اس سال کا وزارت تجارت کا بجٹ ہے - گذشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بجٹ استی میٹ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس کے نام سے نمبر ۲ پر بجٹ ایسٹی میٹس میں صاف طور سے کہا گیا ہے -

"The Budget Estimates 1982-83 a decrease of Rs. 80.12 crores compared to Revised Estimates of 1981-82."

یعنی اس سال ہینڈ لوم کی مد میں ۸۰ کروڑ بارہ لاکھ ۳۹ ہزار روپئے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس سے کم کر دیا گیا - تو آپ خود دیکھیں کہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے - ہر مد کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا لیکن اتنا روپیہ نئے بیس سوتری کاریہ کرم کے آنے کے بعد بھی یہ پہلا بجٹ ہے جس میں حکومت نے ہینڈ لوم اور دستکاروں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے اس اسی کروڑ روپئے کو کم کر کے - جب یہ ابتدا ہے تو انتہا کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں اور وہ بھی نئے بیس سوتری کاریہ کرم کے اعلان کے بعد -

PROF. N. G. RANGA: Handlooms exports are going up.

شری اشفاق حسین : ہینڈ لوم کی صنعت کو سوت اور کیمیکل کے مناسب دام پر فراہمی کے لئے ۱۹۸۰ع میں اعلان کیا گیا تھا نیشنل ہینڈ لوم ڈیولپمینٹ کارپوریشن بنایا جائے گا - بجٹ میں بھی پیسہ رکھا گیا لیکن ۱۹۸۰ع کے بعد ۸۲ - ۱۹۸۱ع اور ۸۳ - ۱۹۸۲ع میں ابھی بھی نیشنل ہینڈ لوم ڈیولپمینٹ کارپوریشن کس اسٹیج پر ہے یہ پتا نہیں ہے - اور اس کی ترقی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس سال کی بجٹ مانگوں میں اس مد میں پہلے رکھے گئے دو کروڑ روپئے کی جگہ اس سال اسے گھٹا کر ۷۵ لاکھ ۷۰ ہزار روپئے کر دیا گیا - تو کتھنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کروڑ ۲۴ لاکھ ۳۰ ہزار روپئے کی رقم کم کرنے کا مطلب یہ لگایا جائے کہ حکومت اس کارپوریشن کو وجود میں لانے میں تیزی دکھا رہی ہے یا اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال رہی ہے - ہینڈ لوم کی فروغ کے لئے سوتی ملوں پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ بازار میں فروخت کرنے کے لئے ۵۰ فیصدی سوت ہینڈ لوم کے لئے تیار کریں اور اس ۵۰ فیصد سوت میں سے ۸۵ فیصد سوت ۴۰ نمبر اور اس سے نیچے کے نمبروں میں تیار ہوگا - لیکن پوزیشن کیا ہے - ۱۰ لاکھ ۶۷ ہزار کلو گرام سوتی دھاگے میں سے صرف ۲ لاکھ ۶۰ ہزار کلو گرام ہینڈ لوم کے لئے تیار کیا گیا ۸۲ - ۱۹۸۱ع میں - ایسی پابندی لگانے سے کیا فائدہ جس پر عمل کی ذمہ داری لینے کے بعد بھی عمل نہ ہوتا ہو - یہی وجہ ہے کہ نیشنل ہینڈ لوم ڈیولپمینٹ کارپوریشن ابھی تک وجود میں نہیں آیا اور اس سال اس کے لئے روپیہ بھی کم کر دیا گیا - ہینڈ لوم کے مناسب دام کی فراہمی کے لئے ضروری ہے کہ ۵۰ فیصد اور ۸۵ فیصد کی جو قانونی پابندی ۱۹۷۸ع میں لگائی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کیا

[شری اشفاق حسین]

ہینڈ لوم کو عزت کا مقام دیا گیا ہے - نائب وزیر صاحب - ڈپٹی منسٹر صاحب کا جو بھاشن ہوا ہے میں تو تین سال سے بھاشن سنتا آ رہا ہوں کہ ہینڈ لوم کو عزت کا مقام دیا گیا ہے لیکن وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے -

یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی کپڑے کی ساری ضرورت ہینڈ لوم سے پوری کی جائے گی - لیکن کنٹرولڈ کپڑے میں جلتا ساری میں ہینڈ لوم کو سبسڈی ایک روپئے ۵۰ پیسے فی اسکوئر میٹر دی جاتی ہے جب کہ ایپن - ٹی - سی - ملوں کو اس طرح کی ساری کے لئے دو روپئے ساری دی جاتی ہے - ہینڈ لوم کا جو کپڑا تیار ہوتا ہے وہ غریب تیار کرتے ہیں اور غریبوں کے لئے تیار کرتے ہیں لیکن ان کو بڑھاوا دینے کے لئے سبسڈی صرف ڈیڑھ روپئے دی جاتی ہے اور ایپن - ٹی - سی - جب وہی کپڑا تیار کرتا ہے تو دھوتی ساری کے لئے اس کو دو روپئے کی سبسڈی دی جاتی ہے - یہ فرق کیوں ہے مجھے معلوم نہیں منتری جی کو اس بارے میں بتانا چاہئے -

یہ اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ ایپن - ٹی - سی - ملیں سرکار کی ہیں اور ان کا گھاٹا نفع دیکھنے کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہے اور غریب جائے - اگر آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ملوں پر پابندی لگانی ہوگی - کہ مقررہ مقدار میں سوت ہینڈ لوم کے لئے تیار کریں - اور میرا سجھاؤ ہے کہ جب ہم چینی اور سیمینٹ کی دوہری نیتی اپنا سکتے ہیں تو ہینڈ لوم کے دھاگے کی فراہمی کے لئے بھی کیا دوہری نیتی نہیں اپنا سکتے ہیں - اس پر منتری جی وچار کریں اور صاف جواب دیں -

ہینڈ لوم کے لئے دوسری اہم ضرورت اس کے لئے لگے ہوئے دائرے پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے - چھوٹر بنا دئے گئے کہ ہینڈ لوم پاور لوم اور ملوں پر یہ کپڑا بنے گا - لیکن کیا اس پر عمل ہوتا ہے - ہاں یہ رہا ہے کہ جو کپڑا ہینڈ لوم پر بننا چاہئے وہ کپڑے عام پاور لوم پر بن کر بازار میں آ رہا ہے اور پاور لوم پر بنانے والا کپڑا ملوں کے دوبارہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے - کسی بھی پابندی پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے کاغذ پر ہو تو ہو - ان دونوں کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے جس میں کوتاہی اور ڈھلائی حکومت برت رہی ہے - موجودہ ٹیکسٹائل پالیسی میں یہ ڈھنڈھورا پیٹا گیا ہے کہ

۱۹۸۰-۸۱ع اور ۱۹۸۱-۸۲ع کے بجٹ میں ہینڈی کرافٹ کی مد میں پانچ کروڑ پانچ لاکھ روپئے قالین ٹریننگ سینٹر کے نام پر رکھے گئے جو کہ اس سال بالکل ختم کر دئے گئے - پتا نہیں کہاں اس کو مرج کر دیا گیا ہے - ہینڈلوم کارپیٹ جو دیہات کے غریب بنکر تیار کرتے ہیں ان کو اوپر سے سرکار کی نظر کچھ پھر گئی ہے کیونکہ پہلے ٹریننگ کے نام پر جو روپیہ ملتا تھا اس سے انڈسٹری کو بڑھاوا ملتا تھا اور اس ہینڈلوم کارپیٹ سے ہم سیدھے سیدھے ایک طرف ودیشی مدرا ارجت کرتے تھے اور دوسری طرف دیہات کے بنکروں کو فائدہ ہوتا تھا -

ہمارا ملک اپنی دستکاریوں کے لئے بہت مشہور ہے چاہے اتر پردیش میں مرادآباد کے برتن ہوں علیگڑھ کے تالے ہوں سہارنپور کا لکڑی کا کام ہو یا کشمیر کا آئوری کا کام ہو یا اینست میں بانس کا کام کیا جاتا ہے - اس سال کے بجٹ میں ان دستکاریوں میں جو آپ نے ۱۰ کروڑ ۴۹ لاکھ روپیہ رکھا ہے یہ اس بات کا ثبوت نہیں دیتا ہے کہ آپ دستکاروں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں - اس کے لئے ضروری ہے کہ دستکاروں ہینڈلوم کے ساتھ جو اب سوتیلا کیا جا رہا ہے اس میں آپ بلکہ جو دیہات میں رہتے ہیں جس کا تعلق کمزور طبقے سے ہے غریب طبقے سے ہے اس لئے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے - ہینڈلوم کے بنکروں کو عملی ثبوت دینا ہے تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہئے کہ جو سبسڈی ہینڈلوم کو دیتے ہیں وہ این - ٹی - سی - سے بڑھا کر دیں - اگر این - ٹی - سی - کو دو روپئے دیتے ہیں تو ہینڈلوم کو ڈھائی روپئے دیں -

پچھلے سال کے مقابلے ہینڈلوم اور این- ٹی- سی- کو دی جانے والی سبسڈی کی رقم کم کر دی گئی ہے - سبسڈی کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہینڈلوم کا کپڑا بھی کم تیار ہوگا - جو کپڑا جتنا کھڈے کے نام سے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ رقم اس مد میں اس سال آپ نے کم کر دی ہے - آپ تو لائق ہیں ہونہار اور نوجوان ہیں اور آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اس لئے آپ کو خاص طور سے سمجھنا چاہئے کہ اس سال جو آپ نے روپیہ سبسڈی کی مد میں دیا ہے وہ قریب ۵۷۵۵۰ کروڑ پچھلے سال کے مقابلے میں کم کر دیا ہے - اس طریقے سے تقریباً ۵۸ کروڑ روپیہ کم کرنے سے کیا ہینڈلوم کو بڑھاوا ملے گا - کیا اس طرح سے ہینڈلوم کی ہمدردی کا یہی عملی کام ہے -

[شری اشفاق حسین]

کمی کریں اسے ختم کریں - انہیں برلوری کا درجہ دیا جائے - چونکہ وہ کمزور اور پچھڑے ہوئے ہیں اس لئے انہیں اور پروتساہن اور پروٹیکشن دینی چاہئے -

سبھاپتی مہودے (شری ہری ناتھ مشرا) : میں آپ سے درخواست کرونگا کہ آپ اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کریں -

شری اشفاق حسین : میں مانگ کروں گا کہ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس کی ایک الگ سے وزارت قائم کی جائے -

جو نئی ایکسپورٹ پالیسی گھوشت کی گئی ہے - بہت سے ساتھیوں نے اس پر کہا ہے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ وقت کم ہے اس لئے میں شری اندر جیت گپتا کی تقریر کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے اس میں اور کچھ جوڑنا نہیں چاہتا -

گارمینٹس کے ایکسپورٹ کے سلسلے میں ایک نیا اعلان اخباروں میں دیکھنے کو ملا ہے - جس میں گارمینٹس اور فیبرکس کے سبھی طرح کے کوٹے کو خلط ملط کر دیا گیا ہے - ایک میں مکس کر دیا گیا ہے - اس سے ہینڈلوم اور فیبرکس کا خصوصی کوٹا ختم ہو گیا ہے - اس سے ہینڈلوم اور دستکاریوں کو نقصان پہنچے گا -

اپیریل ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے گھپلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کے عہدے داروں کی بے ایمانی کی طرف آپ کا دھیان دلاتے ہوئے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں خصوصی توجہ دی جائے -

جہاں تک جوٹ کا تعلق ہے یہ آپ کے ریاست سے تعلق رکھتا ہے -

سبھاپتی مہودے : بنگال اور کچھ حد تک بہار -

شری اشفاق حسین : وہاں پر دو جوٹ ملیں ہیں - کٹیہار جوٹ مل کو بد انتظامی کی وجہ سے سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور امید ہے کہ اب وہ صحیح چلے گی - لیکن جو دوسری مل وہاں پر ہے - اس کو کلکتہ کے کوئی سیٹھ چمریا چلاتے ہیں - وہ اس جوٹ مل پر کم دھیان دیتے ہیں اور کلکتہ میں اپنے چمڑا ادیوگ پر زیادہ دھیان دیتے ہیں - مزدوروں کی کئی مہینے کی تنخواہ اور گرچویٹی پھنسی ہوئی ہے - ان کا بونس بھی رکا ہوا ہے - ڈیڑھ کروڑ روپئے کی رقم ان پر باقی ہے - اس مل کو نیشنلائز کیا جائے تاکہ مزدوروں کو مزدوری ملے اور جوٹ ادیوگ کی بھی ترقی ہو -]

SHRI DAULATSINHJI JADEJA (Jamnagar): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Commerce. While doing so, I shall restrict my observations to trade with a distant region and a few selected commodities.

It is gratifying to note that over the last couple of years, there has been an increasing realisation in India of the promising opportunities for developing Indo-Latin American economic relations.

These efforts began in early forties, when the Government of India opened the Office of Trade Commissioner in Buenos Aires, Argentine. Notwithstanding these early efforts, our economic links with Latin America did not really begin till the historic visit of our Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi in 1968. Since then, the growing participation by India in various international economic forums such as UNCTAD, TCDC etc. offered Latin American countries an opportunity to appreciate India's immense economic and technological advances.

The near collapse of the world monetary system and the continuing recession has made it imperative for India to diversify our international trade relations. While inaugurating the New Delhi consultations among the developing countries recently, our Prime Minister rightly stressed the need to make economic cooperation among developing countries a vast movement.

In spite of all this emphasis, I am sorry to say that there has been very little concerete achievement in the Indo-Latin-American Trade relations.

To enumerate some points, I feel that the following give indications of the present state.

Absence of direct Shipping service between India and Latin America has so far been the major limiting road in promoting steady flow of commodity trade between India and Latin America. While the present Shipping arrangement of the Shipping Corporation of India for accepting cargo for South-America destinations with trans-shipment point in Singapore has proved somewhat unsatisfactory, but the Shipping Corporation's very recent successful efforts to have tie up with a South American line, as well as the announcement by Colombia to establish a direct shipping service with India are efforts in the right direction. I do not have to elaborate on the rich prospects that exist for India's traditional and non-traditional exports to Latin America. A number of trade delegations that have visited Latin America have identified these possible areas of trade.

Equally, Latin America is capable of meeting a wide-range of India's import needs, important among them being petroleum and non-ferrous metals and uncut diamonds. India has entred into contracts with Mexico and Venezuela for petroleum crude. It is my earnest hope that these contracts will prove to be just the beginning of the trade exchanges between India and Latin America.

A right step was taken when fishing trawlers were imported from Mexico in the middle 70s. But since then, stronger links with that region were not forged. Latin America has one of the best developed fishing industries. Peru is the world's leading producer of fish. Tuna, Shrimp and al varieties are fished in Latin America. Yet, we have been unable to conclude even one joint venture agreement with Latin American countries in the fisheries sector.

At the present moment, it would have been interesting and valuable for India to explore the experiment that Brazil is carrying on, using molasses based alcohol to fuel motor transport. A similar situation exists in India, whereby the experiments could be carried out, as presently Brazil gets 20 per cent of its fuel needs supplied by alcohol produced from molasses.

The technologies that Latin American countries buy from the West are capital—intensive. They do not suit many of the tropical countries of the region. India could certainly play a leading role among these countries in supplying the tropi-

[Shri Daulat Sinhji Jadeja]

calised labour-intensive technolgies for several Latin American countries.

Such an exchange of technology can be encouraged by posting scientific Attachees in our Embassies. It is also necessary to encourage programmes of exchange at the academic level and also between specialised research institutions.

It would be appropriate if various trade and commercial officers could be given specific targets to fulfil. I would like to point out that some of the Amazonian countries had asked for Indian buffaloes. But I am informed that due to delay in communication, nothing fruitful has materialised. Animal husbandry and agriculture is one field where there is good scope for cooperation.

It would be a mistake to assume that Latin America can wait till we have the time to develop our relations with them. Japan and Korea have followed the lead of Canada and now they have made great progress in fostering mutual trade with Latin America.

We have an inherent advantage in Latin America, in that there is a general sympathy and appreciation of our history and culture. There is no bias of any sort against us. On the contrary, India would be welcome because we do not belong to the dominating economies.

We must continue to send trade and cultural delegations to Latin America. Our communication with that region must be improved.

Government must initiate steps to make it worthwhile for Indians to explore possibilities of developing trade with Latin America. A scheme of incentives must be granted for this purpose. If incentives are given, Indian businessmen would definitely take advantage of the posibilities.

In conclusion, may I reiterate that increasing the two-way trade and economic cooperation between India and Latin America needs no more emphasis? That rich possibilities exist in mutual economic relations between India and Latin America, is obvious.

What is, however, imperative is a strategy coupled with a conscientious effort in understanding each other better, through more and more personal contacts at official, business and educational levels. An effort indeed is to be made to project earnestly the modern image of India, highlighting importantly the giant strides that our country has made in the fields of science and technology.

The former Commerce Minister, Shri Pranab Mukherjee has more than once assured that high priority is being given to the promotion of trade and economic relations with the Latin American region. He has also assured that trade and industry in India will be given the necessary facilities and support for effective implementation of the oportunities available.

It is my earnest hope that our Government will turn a new page in our trade and economic relations with the countries of Latin America and the Carribean, many of whom share the same aspirations as we do.

Coming back to our own land, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the policy of importing dates and exporting onions. This was a reserved item to help the small man, i.e. the sailing vessel owner. It has traditionally been the trade of the sailing vessel owner; but lately, even the bigger shipping companies have been allowed to import dates, when sailing vessels were available at Dubhai and other places.

I would only request the hon. Minister to clarify this policy of ours, and tell us whether the sailing vessel industry, which is an industry of the common man and the small man will be saved by our Government's policy or not.

Talking of the free trade Zone, I come from a region where we have the Kandla Free Trade Zone. The Kandla Free Trade Zone has expanded its territorial area to the other coast, viz., the coast of Saurashtra; and a small village called Wednar has already been included as part of the off-shore Kandla project. May I request Government to tell us whether

they will allow the Free Trade Zone to be expanded, so that the Wednar area could also be covered for the Free Trade Zone activity?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Sir, I conrgratulate Madam Gandhi for entrusting this very important Ministry to two young men of our House; and I am also glad that Minister is ably assisted and his orders are being executed by very efficient officers who have travelled all over the world, and who have worked in U.N. and other places.

Before proceeding with my speech, I want to answer one point of Mr. Indrajit Gupta. He referred to Keshav Ram Textile and Jute Mills of Calcutta, which employs over 10,000 persons; and there is a strike. That factory was making over Rs. 3 crores. to Rs. 4 crores. This self-same management, viz. Keshav Ram Mills are having a cement factory in my State; that factory's capacity has been increased by 300 per cent over 15 to 20 years. That also makes a profit of Rs. 2 crores to Rs. 3 crores; and its production is over 120 per cent. It is the same management in two different States. What is the difference? I think there is something wrong with the State Government and its labour leaders. But in my place, my government gives all the assistance to the labourers and labourers are getting very good incentives to produce more. There is a shortage of coal and electricity. In spite of that, the production is over 120 per cent. That is due to the management over there. Simple because he is Birla, we should not go on condemning. That is the habit unfortunately with our communist members. He has also referred to the strike in Bombay. As the Minister knows and the former Chief Minister is here, who has been working day-in-and day-out to build up the Maharashtra State which is number 1 State in our country.....

MR. CHAIRMAN: I think he has been planning now for the entire country.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Now he is planning for the entire country. once upon a time, he was confining to Andhra Pradesh and Maharashtra. He is from my place and my university. There what I understand is that, because I am also a frequent visitor to Maharashtra, they have created a violent situation. The people are afraid of going to work. Now, I request the Centre and also the Maharashtra Government to give security to the workers and also they should be assured of their safety. Then immediately all the mills will start producing.

The good thing is that we are exporting a lot of articles from our country to other countries. Our officials, the STC and MMTC create a market. Suddenly, one fine morning one item is withdrawn and all our effort in creating the market go waste. I want that, whenever they create a market, we must feed it; we must supply; we should be dependable suppliers. When we have got plenty, we will export more.

Take for instance sugar. Sugar, as a matter of fact, built up our foreign exchange reserve, because we exported it. Once myself, Vasant dada and our sitting members went to Madamji and requested her to export sugar. At that time, we earned Rs. 460 crores as foreign exchange plus made a profit of Rs. 150 crores. That is the basis at that time. Later on, this gult movement and other things came and out foreign exchange reserve went upto Rs. 5000 crores. Unfortunately, when the Janata Government came, they squandered it. Then we built up about one crore tonnes foodgrains reserve which they had also squandered and had created the scarcity.

MR. CHAIRMAN: I think it had been 2 crores.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I am talking of the balance reserve in our godowns.

दो करोड़ का बढ़ाया था मगर एक करोड़ गोदाम में था ।

शूगर को ले लीजिए । जब मेडम गांधी पावर में आई 1980 में, तो शूगर

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी[

का प्रोडक्शन हमारे देश में 36 लाख टन था लेकिन मेडम की पालिसी की वजह से यह 52 लाख टन हो गया ।

सभापति महोदय : गन्ने को जला दिया जाता था खेतों में ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: उस की वजह से प्रोडक्शन गिर गई, सभापति जी ।

सभापति महोदय : मैं उसी पृष्ठभूमि में कह रहा हूं कि शूगर की कमी हो गई थी ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस साल 75 लाख टन शूगर पैदा होने वाली है । 75 लाख टन हमारा प्रोडक्शन होगा और मेक्सीमम कन्जम्पशन हमारे यहां 55 लाख टन होगा । बाकी जो सरप्लस प्रोडक्शन है, वह 20 लाख टन होगा । इन्टरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिहाज से करीब 7 लाख टन शुगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं । तो मंत्री जी यह जो 13 लाख टन शूगर और बचेगी, इस का क्या होगा और आयन्दा भी इतनी ही शूगर पैदा होगी या इस से ज्यादा हो सकती है और इस में महाराष्ट्र ने लीड ली है । हमारे मंत्री जी ने गांव-गांव में जाकर वहां पर कोआपरेटिव शूगर फ़ैक्ट्रीज लगाई और जहां पहले शूगर के मामले में यू० पी० न० 1 पर था वहां अब महाराष्ट्र हो गया है ।

एक बात और कहूंगा । राईस-ब्रान एक्सट्रेक्शन हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं । अभी तक उस के एक्सपोर्ट कोटा का एनाउन्समेंट नहीं हुआ है । मुर्गियों के लिए जितनी आवश्यकता हो, उस को आप रख लीजिए लेकिन बाकी जो है, उस को तो एक्सपोर्ट कीजिए । पूरा एक्सपोर्ट बन्द कर दिया, यह कौन सा तरीका है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । आज तक जो मुर्गियों को खाने वाले हैं उन से भी मुर्गियों को निकाल कर आप इन से फ़ौरन एक्सचेंज कमा सकते हैं । अगर इनके अंडों को एक्सपोर्ट किया जाए तो इस तरह से एक-एक पैसा मिला कर हम 40 करोड़ रुपये तक का फ़ोरन एक्सचेंज कमा सकते हैं । मैं मानता हू कि हमारे मंत्री जी एक्सपोर्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं । लेकिन अगर हम इस चालीस करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट को इससे निकाल दें तो हमारी कितनी फ़ोरन अर्निंग्स कम हो जाती हैं ।

जो आइटम्स हमारे यहां साल की साल पैदा होती हैं उनकी एक्सपोर्टस की अर्निंग्स पर हमें कमी नहीं करनी चाहिए । दिन-प्रति-दिन उन आइटम्स की एक्सपोर्ट बढ़ाते जाना चाहिए । हमारी ज़मीन से जो भी पैदा होता है वह तो हर साल पैदा होता रहेगा । हमारे यहां मुर्गे और मुर्गियां भी पैदा हो सकती हैं । इनका जितना चाहे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं । इन चीज़ों के एक्सपोर्ट में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए ।

अब आयरन ओर तो हमारी धर्म निधि है । इसको जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया जाना चाहिए । इसके एक्सपोर्ट में हम कमी ला सकते हैं । लेकिन चावल जो हमारे यहां काफ़ी है, उसका एक्सपोर्ट आप क्यों बन्द कर देते हैं ? हमारे यहां चावल की कमी नहीं है । हमारे आंध्रप्रदेश में तो यह मुसीबत हो रही है कि चावल बिक नहीं रहा है । महाराष्ट्र में उसे हम ले नहीं जा सकते । महाराष्ट्र का और मेरी कांस्टीच्युन्सी का बार्डर मिला हुआ है । चह्वाण साहब की कांस्टीच्युन्सी और मेरी कांस्टीच्युन्सी मिली हुई हैं । अब क्या करते हैं खाना बना कर महाराष्ट्र में ले जाते हैं । बीच में

नदी पड़ती है । उसके बीच में से पानी में से ले जाते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह से इन सब चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ाते रहना चाहिए ।

मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक्सपोर्ट मार्टिक मेहनत से पैदा की जाती हैं । हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है । परसों ब्रिटिशर्स की एक मीटिंग में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्री है और वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है । हम अपने पांवों पर खड़े हैं । हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ।

हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिये । मैं 10-12 आइटम्स लिखकर लाया हूं जिनको मैं मंत्री जी को दे देता हूं । मंत्री जी इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मेहरबानी करके एक्सपोर्ट करा दीजिए । फोरन मार्किट में हमारी जो सुप्रीमेसी है वह बाकायदा बनी रहे ।

आपने बैंक गारन्टी एडवांस कर दी है और अब 5 हजार 9 सौ तक आप द रहे हैं यह बहुत बड़ी चीज है । पहले 3 हजार 8 करोड़ तक भी नहीं थे । इस तरह से एक्सपोर्टर्स के रास्ते में जो कई चीजें बाधा थीं वह भी आप निकाल दीजिए । मैं जानता हूं कि आप क्रिटिसिज्म से नहीं डरते हैं । आप स्प्रिट वाले आदमी हैं आप किसी चीज में कितनी सच्चाई है, इसको देखते हैं । मैं जानता हूं कि आपके नीचे हमारी पालिसी बिना दबाव के अच्छी बनती जाएगी ।

मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दो नौजवान मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं । मैं उनको बधाई देता हूं ।

15.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं वाणिज्य विभाग की अनुदानों का समर्थन करते हुये बहुत ही सीमित क्षेत्र में अपनी बातें कहूंगा ।

श्रीमन्, हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से, हमारे जिले मिर्जापुर और भदोही में कालीन उद्योग बहुत पुराना है। इस उद्योग में इस इलाके में लगभग पांच लाख आदमी काम करते हैं । यह सारा काम देहातों में होता है । गांवों की झोंपड़ियों में बुनाई, रंगाई, ढुलाई का सारा काम होता है और यह विशुद्ध काटेज इंडस्ट्रीज है । इस देश में इसकी खपत कम है । इसका निर्यात होता है ।

श्रीमन् यह हमारे क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण उद्योग है कि यह वहां की जनता के जीवन-मरण का सवाल है, किन्तु दुर्भाग्य से पिछले वर्ष से यह उद्योग संकट में है । इस बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी भूतपूर्व मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं कि इस बारे में कदम उठाये जायें ।

यहां पर जो कालीन बनाया जाता है उसका मार्केट जर्मनी में है । वहां पर मुझे पता चला है कि जर्मनी में करेंसी का डीवलुएशन हो गया है, जिससे कालीनों की खरीददारी बन्द हो गई है और बहुत सा माल जर्मनी में पड़ा हुआ है, उसका पैसा आना बन्द हो गया है । इससे वहां की जनता को बड़ा धक्का लगा है । इसके बारे में प्रधान मंत्री जी से और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री जी से इस समस्या के बारे में निवेदन किया था 4-5 लाख लोगों के जीवन का सवाल

[श्री उमाकांत मिश्र]

है और साथ-साथ करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा खतरे में है, इसलिए इस उद्योग को जिन्दा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाये जायें। मुझे बहुत सन्तोष है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है और अब कुछ ऐसा लगा है कि कालीन उद्योग संकट से उबर रहा है। मैं इस बारे में बहुत विस्तार से भाषण न देकर इतना ही कहना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, लेबर ओरिएंटेड है और इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। लाखों लोग इसमें काम करते हैं। हमारे क्षेत्र की तो यह जान है। एक समय तो हमने यह कहा था कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई और उद्योग नहीं चलाना है तो हमारे जो पुराने उद्योग हैं, कालीन उद्योग है, हैण्डलूम उद्योग है, सिल्क उद्योग है, साड़ी उद्योग है, इनको गांवों तक फैला दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए। इससे वहां के लोग रोजी कमा सकते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। इसके लिए आप सहायता दीजिए। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी, अब यहां लोक सभा में कालीन उद्योग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव, निवेदन और मांगें मैं उल्लिखित करना चाहता हूं।

इस समय कालीन उद्योग में बड़ा भारी संकट बन गया है। जो सुविधायें ऋण की बैंक से मिला करती थीं, उसमें बड़ी बाधा पड़ रही है। एक बड़ा कालीन बनने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है और बैंक से ऋण 80–90 दिन के लिए मिलता है। इतने समय में कालीन तैयार नहीं होता, इसलिए ऋण की सुविधा इस बात को ध्यान में रख कर दी जाये और समय की लिमिट को बढ़ाया जाये।

इस समय जर्मनी में माल पड़ा हुआ है। वहां से खरीदार आते हैं और अच्छे किस्म के आर्डर देकर चले जाते हैं। माल जब जाता है तो पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं कि माल खराब है इसलिए 20–25 प्रतिशत छूट दी जाए। एक्सपोर्टर बुनकरों से कहता है और अन्तत: इसका असर बुनकरों पर पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैंक से जो सुविधायें दी जा सकती हैं वे सुविधायें इनको दी जानी चाहियें।

एक बात और बताना चाहता हूं। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने हमारे देश के मुकाबले एक चौथाई कालीन निर्यात किया था और आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले ड्योढ़ा निर्यात कर रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने इस उद्योग को काटेज इंडस्ट्री माना है। आप भी कालीन उद्योग को कुटीर उद्योग घोषित कीजिए और इसको प्रियारिटी सेक्टर में रखिये। इसको अधिकतम सुविधायें दी जायें ताकि इस उद्योग को बढ़ावा मिले। कालीन उद्योग पिछड़ गया है। चीन हमारे से पीछे था वह भी आगे बढ़ गया है। अमरीका आदि के नये बाजारों की तलाश की जानी चाहिये। साथ ही कालीन उद्योग को आप प्रोयोरिटी सैक्टर में लायें। इसको शुद्ध कुटीर उद्योग, स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री घोषित करें। स्माल स्केल इंडस्ट्री की लिस्ट में इस उद्योग, को रखा जाये और स्माल स्केल इंडस्ट्री को जो सुविधायें बैंकों द्वारा दी जाती हैं, वे इस उद्योग को भी दी जायें।

प्रधान मंत्री जी की कृपा से एक वूलन यान मिल हमारे यहां खोली गई है। बीच में उसका उत्पादन बन्द हो गया था। पिछले साल से फिर से शुरू हो गया है।

इस मिल से वहां की मांग पूरी नहीं होती है । मेरी मांग है कि मिर्जापुर औद्योगिक क्षेत्र में दो वूलन यार्न मिलें और स्थापित की जायें । साथ ही साथ काटन यार्न की भी इस उद्योग में आवश्यकता पड़ती है इस वास्ते कम से कम दो काटन यार्न मिलें भी उस इलाके में स्थापित की जायें। काटन यार्न का जो इस उद्योग के लिए आयात होता है वह भी इससे बन्द होगा और साथ-साथ वहां कुछ लोगों को काम भी मिल सकेगा ।

कालीन एसोसिएशन जो वहां की है। उनकी तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी यह मांग आई थी कि कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सल बधोही मिर्जापुर में खोली जाये । इसकी घोषणा लोक सभा में राज्य मंत्री जी ने भी की थी और कहा था कि इसका गठन किया जाएगा और इसका हैडक्वार्टर बधोही में रखा जाएगा । लेकिन आज तक वह मामला खटाई में पड़ा हुआ है । वाणिज्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि काउन्सिल शीघ्रातिशीघ्र स्थापित की जाये और इसका हैडक्वार्टर बधोही में रखा जाये।

बधोही मिर्जापुर के लोग लगभग दो अरब के कालीन बनाते हैं और उनका निर्यात करते हैं। वे ईरानी, चीनी, परशियन, रोमानियन माडल्स का अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं । क्यों न वहां एक इंस्टीट्यूट ऐसी बना दी जाये ताकि ओरिजिनल स्टाइल के कारपेट वहां व बना सकें और विदेशी ब्यापारियों का एट्रैक्शन बढ़े और कालीनों की खपत विदेशों में अधिक से अधिक हो सके, उनका निर्यात अधिक से अधिक हो सके और भी ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ।

आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कारपोरेशन की एक शाखा बधोही में है, दुर्भाग्य से उससे कालीन उद्योग को लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक हो रही है। जो लोग उसमें काम करते हैं वे इस उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय निजी लाभ को बढ़ावा दे रहे हैं । विदेशी वायर जब आते हैं तो वे उनसे मिल कर लोकल जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उन्हीं का माल खरीदवा देते हैं और उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं । ऐसा करते करते वे बाद में खुद भी एक्सपोर्टर हो गये हैं। जो छोटे-छोटे एक्सपोर्टर हैं, 10, 8 या 5 या 3 या 1 लाख का एक्सपोर्ट--करने वाले हैं उनको बढ़ावा नहीं मिला है । मैं समझता हूं कि इस शाखा में बहुत तेजी से सुधार की आवश्यकता है, नए सिरे से इसका गठन किया जाना चाहिये, बुनकरों के प्रतिनिधि, छोटे छोटे एक्सपोर्टर्ज के प्रतिनिधि, स्थानीय जनता के प्रतिनिधि उसमें लिए जाने चाहियें । यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि जो एक दो या पांच सात लाख का एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके माल को ही खरीदा जाए, उन्हीं का माल बाहर भेजा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन बड़े बड़े मगरमच्छों से सांठगांठ करके वे रुपया न कमा पायें। इससे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्ज को बढ़ावा नहीं मिल सका, बुनकरों को बढ़ावा नहीं मिल सका । इन दिशा में इस कारपोरेशन में वहां सुधार लाया जाना चाहिये। वहां बहुत ज्यादा धांधली है। इसको आप देखें।

बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, वे बुनकरों को धोखा देते हैं । जो माल वहां गया और माल का पैसा यदि उनको देना हुआ तो कह दिया कि जर्मनी में हमारा ग्राहक 25 परसेंट कम दे रहा है इस आधार पर मजदूरों की मजदूरी काट लेते हैं । इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इस उद्योग में काम करने वालों का शोषण न हो ।

[श्री उमाकांत मिश्र]

जहां तक सम्भव हो, कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यक कदम सरकार उठा सकती है वह मैंने बताये, साथ ही एक बात और कहनी है कि 20 परसेंट इंसेंटिव जो मिलता है मैंने सुना है कुछ उसमें अन्तर कर दिया गया है । मेरा सुझाव है कि इंसेंटिव जो दिया जाता है उसका अधिकतम लाभ बुनकरों को मिलना चाहिये । होता यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग कारपेट खरीद लेते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंसेंटिव उनको एक्सपोर्ट पर दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि एक्सपोर्ट पर आप इंसेंटिव अलग से दें, मगर एक आइटम ऐसा भी रखें कि कुछ इंसेंटिव मैनूफैक्चरर को भी मिले जो कि कालीन बुनता है । यह बहुत बड़ी हस्तकला है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है और कई लाख लोगों को काम मिलता है। इसलिए इंसेंटिव का लाभ बुनकरों को मिले और छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को मिले ।

इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कालीन उद्योग हमारे देश का प्रमुख उद्योग है और पिछले साल 175 करोड़ का निर्यात हुआ और इस वर्ष शायद 125 करोड़ का निर्यात हुआ, तो इस विदेशी मुद्रा देने वाले धंधे को बढ़ावा देने के लिए मेरी अपील है कि सरकार ऐसे कदम उठाये जिससे अधिक से अधिक लाभ गरीब बुनकरों को मिले ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो और साथ ही अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देश को मिले ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मगो का समर्थन करता हूं । आज हमारे देश का बहुत सा पैसा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर जा रहा है, एडिबिल आयल विदेशों से लेना पड़ता है, फर्टिलाइजर पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है और न्यूप्रिन्ट और सीमेंट का आयात करने में हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नेपानगर में हमारे देश का बहुत बड़ा न्यूजप्रिन्ट का कारखाना है और जो 4 लाख 10 हजार टन की न्यूजप्रिन्ट की मांग है उसकी 15 प्रतिशत मांग इस कारखाने से पूरी होती है, इसलिए इस कारखाने को प्रोत्साहन देना चाहिये । उस मिल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कभी बिजली का संकट, कभी उत्पादन को मार्केट में बेचने का सवाल आ जाता है । जैसे कि अभी पिछले दिनों एस० टी० सी० ने बहुत सा न्यूजप्रिन्ट बाहर से मंगा लिया था और नेपानगर मिल का कागज स्थानीय मार्केट में नहीं निकला जिस वजह से इस मिल को 1 और 2 सिफ्ट्स में ही चलाना पड़ा, बजाय 3 शिफ्ट्स के जिसके कारण उस कारखाने की औद्योगिक क्षमता का पूरा लाभ हम नहीं उठा रहे हैं । इसी तरह ऐडिबिल आयल में 700 करोड़ रु० विदेशों को देना पड़ता है पिछले दिनों मुझे नेशनल डैरीडेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष डा० कुरियन से मिलने का मौका मिला था, लगभग दो वर्ष पहले, और उन्होंने दावा किया था कि वह दो साल में देश का 700 करोड़ रु० जो विदेशों में जाता है उसको बचा सकते हैं। देश में एक समय था जब हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। हिन्दुस्तान का किसान इतना मजबूत है कि अपने ही देश में तिलहन की फसल को उत्पादित करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, यह उनका दावा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी इस मांग की बारीकी से जांच करवाकर उसे अमल में लाया जाये ।

मुझे खुशी है कि हमारे देश में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सप्लोरेशन पर हमारा शासन और हमारी प्राइम मिनिस्टर काफी ध्यान दे रही हैं और इससे हमारे देश में नये-नये तेल के स्रोत हमको प्राप्त हो रहे हैं जिससे हमारी बहुत सारी फारेन एक्सचेंज, जो विदेशों को चली जाती है, उसे हम बचा सकते हैं ।

मिनी सीमेंट के प्लान्ट हमारे देश में उस जगह पर लगाये जायें जहां रा-मटीरियल प्राप्त होता है, इससे भी काफी पैसा हम देश का बचा सकते हैं ।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां कि 17 हजार पावरलूम हैं। 31-12-79 तक वहां पर जो अन-अथोराइज्ड पावरलूम थे, उनको अथोराइज करने के लिए लोगों से प्रार्थना पत्र मंगाये गये थे, लेकिन अभी तक 1,000 लोग ऐसे हैं हैं जिनको एल-4 के लाइसेंस नहीं मिले हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी एल-4 के लाइसेंस देकर उनके पावरलूम को अथोराइज करने की कृपा करें ।

यह देखने में आता है कि चाहे हैंडलूम सेक्टर के लोग हों या पावरलूम सेक्टर के लोग हों, जो गरीबी आज से से 20, 25 साल पहले थी, वही हालत आज भी उनकी है । उन्होंने कितने करोड़ मीटर कपड़ा बना दिया, लेकिन अपनी जमीन से वह उठ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है वह मास्टर वीवर है। मास्टर वीवर ने अपने पैसे के बल पर मजदूर के रूप में उनकी हालत बना रखी है, वह अपने आप में उठ नहीं पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम, चाहे पावरलूम से उत्पादित कपड़ा हो या हैंडलूम से उत्पादित कपड़ा हो, उसको वेअर हाउसिंग और मार्केटिंग की फसिलिटी नहीं देंगे तब तक बिचौलिये उसका अपना लाभ प्राप्त करने के लिए कम कीमत पर खरीद लेंगे और उनका उसको पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा और वह लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते ।

हमको कोशिश करनी चाहिये कि जगह-जगह पर उनकी को-आपरेटिव सोसाइटीज बनें, उनको मजबूत करें और आर्थिक मदद दें और उनके माल को ठीक समय पर खरीदकर स्टोर करें और उनसे जो बीच के लोग प्राफिट कमाते हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाकर हमारे देश में जो पावरलूम फैडरेशन बनी है, उसमें बुरहानपुर को दिया जाना जरूरी है। हमारे मध्यप्रदेश में बुरहानपुर पावरलूम का एक ऐसा बड़ा सैंटर हैं जहां पर 17 हजार पावरलूम चलते हैं जहां से काफी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है ।

इसलिए जो नेशनल फैडरेशन आफ पावरलूम है, उसमें आवश्यक है कि हमारे मध्यप्रदेश के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

आज एक बड़ी समस्या हमारे देश के किसानों के सामने उपस्थित हो गई है। हमारे यहां से जो काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया कपास खरीदता था, पिछले दिनों से उसने या तो बिल्कुल नहीं खरीदा है या एकदम एक्सपोर्ट प्राइस पर खरीदने लगा है । इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और काफी बड़ा संकट उनके सामने आ गया है । आज से 1 महीने पहले कपास के दाम 460 रुपये क्विंटल थे अब वह एकदम गिरकर 350 रुपये क्विंटल पर आ गये हैं। इस तरह से व्यापारियों की

[श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर]

मनमानी हिन्दुस्तान की कपास की मंडियों में चल रही है और किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एक और किसान का फर्टिलाइजर मंहगा हो गया है और दूसरी ओर उसके उत्पादन की कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। अगर ऐसे समय में उसको ज्यादा पैसा नहीं दिया तो वह लड़खड़ा जायेगा और रूक नहीं पायेगा। उससे न केवल किसान प्रभावित होंगे बल्कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जैसे एक बार अगर हम शुगर-केन का अच्छा पैसा नहीं देते हैं तो दूसरे साल शक्कर का कमी पैदा हो जाती है, कहीं ऐसा न हो जाये कि हमारे देश के इन किसानों को कपास का पैसा न मिलने से कपास की तकलीफ हमारे देश में हो जाये।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को विशेषकर नोट कर लें और आज से एक महीने पहले कपास की खरीदी जो काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया करता था, उसी ढंग से सारे हिन्दुस्तान की मंडियों में उसी दर से वह कपास की खरीदी करे। जिस तरह देश के उद्योगतियों को एक्सपोर्ट के लिए बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं, यह खुशी की बात है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि नई शुगर फैक्टरीज केवल कोआपरेटिव सैक्टर में होंगी। यह निर्णय प्रशंसा के योग्य है। इससे देश के किसानों में एक नई आशा जगी है और वे अपने कोआपरेटिव बना कर नई नई शूगर फैक्टरीज स्थापित कर रहे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में वहां के किसानों के सहयोग से एक शूगर फैक्टरी प्रारंभ कर रहा हूं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अड़चनें हैं। नई पालिसी के कारण कंस्ट्रक्शन के लिए पहले सीमेंट का जो कोटा मिलता था वह नहीं मिल रहा है। स्टील भी नहीं मिल रहा है। सरकार पैसे वालों और बड़े उद्योगपतियों को तरह तरह की रियायतें और इनसेन्टिव देती है। किसानों को कोआपरेटिव हमारे शूगर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जरिया है। यदि उनकी नींव मजबूत नहीं बनाई जाएगी, तो हम उसपर एक बुलंद और मजबूत इमारत भी नहीं बना सकेंगे।

मध्य प्रदेश में मेरे क्षेत्र में एल्लू गूंद होती है, जिसे गम कराया भी कहा जाता है। हमारे देश से उसका सात आठ लाख रुपये रोज का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वह रा मैटिरियल के रूप में हमारे देश से बाहर जाता। हमारे देश के उद्योगपति अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि इससे क्या चीज बनाई जाती है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में जांच कराएं और इसकी टेक्नालोजी की जानकारी प्राप्त कर के इसकी इंडस्ट्री को हमारे देश में ही लगाया जाएगा। इससे हमारे जो करोड़ों रुपये रा मैटिरियल के रूप में बाहर चले जाते हैं, उनसे हमारे देश के लोगों को फायदा होगा। दूसरे, इससे हमारे वनवासी लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा।

मंत्री महोदय ने 1982–83 की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पालिसी घोषित की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उससे हमारे देश के उद्योगपतियों में काफी हर्ष है। उसमें जहां निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से काफी उदारता दिखाई गई है, वहीं प्रक्रिया को भी काफी सरल बनाया गया है। उद्योगों को

अनेक मामलों में बिना लाइसेंस के भी अपनी जरूरत का कच्चा माल और सामान आयात करने की सुविधा दी गई है। इस तरह मंत्री महोदय ने उद्योगपतियों को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर दिया है।

1981–82 में हमारा व्यापार का घाटा 5500 करोड़ रुपये का था। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें काफी पैनी और तीखी निगाह रखनी चाहिये। सरकार ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी में जो नरम रुख अपनाया है, कहीं ऐसा न हो कि उद्योगपति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उससे गलत फायदा उठा लें। मंत्री महोदय का यह प्रयत्न होना चाहिये कि उससे देश को लाभ हो, हमारा एक्सपोर्ट अधिक हो, ट्रेडडेफिसिट कम हो, डामेस्टिक कनजम्पशन और लोकल डिमांड अच्छी हो और हमारे माल की क्वालिटी भी सुधरे। नई पालिसी के अन्तर्गत हमने टेकनिकल नो-हाऊ को भी देश में लाने के लिए काफी सुविधा दी है, कई रा मैटीरियल और काम्पोनेंट्स को ओ जी एल के के अन्तर्गत अपने देश में लाने की अनुमति दी है और 85 औद्योगिक मशीनरी के आयात की भी सुविधा दी है। इससे हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की काफी ज्यादा सम्भावना हो गई है। इस पालिसी के कारण हमारे देश के एक्चुअल यूजज और दूसरे लोगों को विदेशी औद्योगिक मशीनें और रा मैटीरियल वगैरह सुगमता से मिलने लगेंगे।

पिछले दिनों कामर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें एक बहुत गंभीर बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। हमारे देश के पब्लिक सैक्टर के उद्योग दूसरे देशों में जो कंट्रेक्ट लेते है, उनमें हमारे देश का बहुत नुक्स न हो रहा है। वे काफी कम कीमत पर वहां काम कर रहे है और साथ ही वे बाहर के देशों से काफी ऊंचे दर पर लोन ले कर बहुत नुक्सान उठा रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों की राय है कि हिन्स्तान के पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर के लोगों के द्वारा एक कनसर्शियम बनाया जाये एक कसार्टिया बनाया जाये जिससे कि सभी में कोआर्डिनेशन हो सके और सभी मिलकर, बाहर के देशों के जो भी कांट्रेक्टस हों, उनसे अच्छा पैसा कमा सकें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पिछड़े जिलों की एक लिस्ट आई थी लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे देश में कुछ पाकेटस ऐसे बन गये है जहां पर पहले कुछ लोग थे और आपकी औद्योगिक नीति के कारण दूसरे उद्योग वहां पर नहीं आ सके और अब वह पिछड़े होते जा रहे है। दूसरी ओर कुछ क्षेत्र जो किसी जमाने में पिछड़े थे लेकिन अब इतने ताकतवर हो गये है कि आगे बढ़े हुए क्षेत्रों को भी उनसे इर्ष्या हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि एक पिछड़ा हुआ जिला जिसको आपने घोषित किया है उनको एक तहसील काफी मजबूत रही हो। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इसका अध्ययन किया जाये तथा पिछड़े हुए जिले घोषित करने के बजाय पिछड़ा हुए तहसीलें घोषित की जायें ताकि देश के पिछड़े हुए क्षेत्र का एक समन्वित विकास किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में कोसा काफी अधिक मात्रा में होती है। रामगढ, बिलासपुर आदि जिलों में कोसा काफी होने के बावजूद बुनकरों को कोई इंसेन्टिव या बैंक से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है। यदि सरकार इससे फारेन एक्सचेंज कमाना चाहता है तो बुनकरों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता

[श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर]

दी जानी चाहिये तथा अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन कराने के लिये किसानों को इंसेन्टिव दिया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश प्रथा तमिलनाडु में किसानों ने रेशम के उत्पादन में बड़ी प्रगति की है। नागोर मे कपास की खेती को रेशम की खेती ने रिप्लेश कर दिया है। सरकार इस बात का अध्ययन करके सारे देश में सिल्क की पैदावार को बढाने का प्रयास करे। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा असम के साथ साथ सारे देश मे किसानों को सरकार प्रोत्साहन देकर अधिक से अधिक सिल्क की पैदावार को बढाये ताकि देश को विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार से खादी के कपडे का बुनकरो को सीधा लाभ पहुंचता है। इसलिये खादी का उत्पादन गांव गांव में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के माध्यम से अधिक से अधिक मात्रा में कराया जाना चाहिये।

आर्युवैदिक दवायें और जडी बूटियां, जिनका उपयोग देश में तो कम है लेकिन विदेशों में इसके प्रति रूचि बढ़ रही है इसलिये इस सम्बन्ध में अध्ययन करके एक्सपोर्ट बढाने की कोशिश की जाये तो ग्रामीण अंचलों में रहने वालों को भी अच्छा पैसा मिल सकता है और विदेशी मुद्रा में भी बढोतरी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने नौजवान लायक मिनिस्टर, श्री शिवराज पाटिल का बहुत आभार मानता हुं क्योंकि वे बहुत अच्छा काम कर रहे है तथा में उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में श्रीमती इन्दिरा सेठ जो है उनके मुनीम साहब ने जो आपके सामने यह मांग रखी है इसको जरा आप सोच लें कि सदन इसको क्यों मंजूर करे? दुनिया में चाहे अमरीका के रीगन सेठ हों या इग्लैण्ड का थैचर सेठ हो या चाहे ब्रैझनेव साहब हो ... (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : थैचर सेठानी।

श्री मनीराम बागड़ी : सेठानी कोई नहीं सभी सेठ है, टाटा या बिडला। तो विदेशों के जो सेठ है उनकी मुनीमों से कम हैसियत है। हमारी कोई साख किसी मण्डी में नहीं है। भारत की किसी भी चीज में कोई साख नहीं है। हमारे यहां कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके मुकाबले में अमरीका या यूरोप की चीजे न आ सके। हमारी एच एम टी की घड़ी देश में जरूर अच्छी है लेकिन विदेशों में नहीं। यह जरूर है कि लोगों के तन से कपड़ा उतार कर बेच दिया जा पैर से जूती छिन कर बेच दी। इसलिये आप बड़े उद्योगों को घटाओ। टाटा, बाटा और बिरला के शरीर को घटाओं तथा गांधी जी की आत्मा को जीवित रखने के लिये खादी और ग्राम में हाथ से बनने वाले जूते और लौहार के काम को आप बढावा दो, तो यह देश बनेगा।

मैं आपसे एक बात और कहना चहाता हूं। नियम 377 के अधीन मैं दो दफा आपका ध्यान आकर्शित कर चुका हूं और मुझे आपसे शिकायत है कि किस तरह के से स्टैनलैस स्टील के अन्दर जो चादर कालो करके आये उसको भी आप पार कर दो और अगर मोड़ कर आये, उस पर डयूटी हो। इस प्रकार देश के जो कारखाने है, वे गिर रहे है और कम से कम हिसार के जो स्टेनलैस स्टील के

कारखाने है, जो छोटे उद्योग थे वे भी सख्त तंगी में हैं।

गुड़ पर बहार जाने से आपने पाबन्दी हटाई और बाहर जाने नहीं दिया, भेजा नहीं, जिससे किसानों को भाव नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का गेहूं दो रु० किलो और डेढ रुपये किलो बिके और डालमिया के कारखाने में जाने के बाद 80 रु० किलो में बिस्कुट बने। कपास किसान के खेत में 350 रु० क्विंटल और जब कल कारखानों में जाये तो 1350 हजार रु० क्विंटल और 2350 और 3350 हजार रुपये क्विंटल हो जाये। इस अन्तर को आपको मिटाना होगा।

आपने घंटी बजा दी है, इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister will reply.

15.57 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair.*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVARAJ V. PATIL): Sir, about 16 Members have participated in this debate. Well, the speeches made by the hon. Members were not fiery speeches but they spoke in a very lucid and constructive manner.

Some of the Members patted the Commerce Ministry on its back and spoke a few good words. The rank and file in the Commerce Ministry values the good words spoken by the hon. Members. It is necessary to evaluate and to criticise to achieve the results. It is also necessary to appreciate and encourage when some good thing is done.

Some hon. Members criticised the working and the policies framed by the Commerce Ministry. The criticisms levelled by them will not be lightly taken by those who are working in the Commerce Ministry. They will certainly attach importance to the points made by them while trying to assess and evaluate the performance of the Commerce Ministry. We attach importance to the criticism also. It gives us an opportunity to correct the mistakes, if there are any, made by us; it gives us an opportunity to dispel some of the misgivings the hon. Members might be having about our policy and so, from both these points of view, the criticism levelled by them is not unwelcome but it is welcome by us.

Sir, the Annual Report is given by the Ministry and it outlines the achievements of the Ministry. It points out some of the draw-backs also and gives the reason as to why the targets which were set were not achieved I hope that the Report will help the hon. Members to follow the direction in which the Ministry wants to proceed.

16 hrs.

Some hon. Members have given cut motions. It is not possible for me now to reply to all the points which are made by hon. Members in the cut motions. Some of the points would certainly be answered in the course of the speech which I am trying to make here but the rest of the points which remain unanswered in my speech will be replied to in writing and the replies will be sent to the hon. Members.

Sir, many points were made by the hon. Members. It may not be possible for me to reply to all the points that are made by the hon. Members who are here but I would like to assure them that we will take into account the suggestions made by them and to the extent it is possible for us to implement those suggestions we will try to implement them. If there are any other kinds of points made by them we will try to send written replies to those points also.

Sir, frist of all I would like to take up the points which relate to the Textile Department and then I want to take up the points which relate to the Forein Tarde Department of our Ministry. The first point which was very cogently made by many hon. Members was about jute. They

[Shri Shiv Raj V. Patil]

said that in West Bengal jute has not helped the peasantry as they are not able to get remunerative price for their jute. The second point which was made by them related to the industry as such.

Sir, it is true that jute prices have been fluctuating and causing lot of concern to the peasants to the industry and to all of us in the Government as well. Now, it is necessary to see that fluctuation in jute price is stopped. With that intention the Jute Corporation of India was brought into existence and the JCI has been purchasing jute. JCI has purchased 17.59 lakh bales this year as compared to 10.62 lakh bales purchased last year. This will go to show that the JCI is doing its best to help the producers of jute in that area. But unless something is done by those who are holding reins of Government in that State it would be difficult for the Central Government to control that thing from here always. Shifting of the responsibility, I would not say, is there but it is necessary to create a machinery to tackle this problem and unless that machinery is available it would be difficult all the time to control that from a long distance. As far as cotton is concerned in certain States cooperative societies are purchasing cotton and as such the question arises why cooperative societies in West Bengal should not purchase jute.

SHRI INDRAJIT GUPTA: There are no jute cooperatives in West Bengal.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If there are no cooperative societies, it would be necessary for the Government to create cooperative societies or any other mechanism for this purpose. I am not trying to shirk responsibility; I am just trying to say that if there are any problems they should be handled by the Central Government as well as the State Governments and others also who are responsible for these things. Secondly, I wish to state about the Various steps which have been taken to see that the jute industry does not suffer. These are the steps taken by the Government of India in order to help the jute industry and through the jute industry the workers in the industry:

(i) Grant of cash compensatory support for export of jute goods with effect from September 1981. Its continuance beyond 31st March is under consideration.

(ii) The emergency purchases of one lakh bales of B.T. Will Bags as one time operation through DGS&D under the Essential Commodities Act and also the repeat orders from the State Governments to set up the off-take of jute bags.

(iii) Compulsory use of new bags for packing cement upto 90 per cent at precent and upto 100 per cent with effect from 1-10-1982.

(iv) Persuading the other user departments to use more jute bags instead of synthetic substitutes for packing of fertilizers, sugar and foodgrains.

(v) Reserve Bank of India has advised all commercial banks to provide additional credit to jute mills for purchase of raw jute upto 14 weeks' consumption including 4 weeks' consumption from JCI and an additional 2 weeks' during November, 1981, to January, 1982, as a measure of price support operation for raw jutes. Banks have also been advised to consider reducing the margin to 10 per cent for purchase of raw jute to be made in November and December and again for purchase to be made in January 1982.

(vi) A Committee of Secretaries has looked into the task-force recommendations on raw jute textiles with regard to demand and supply factors, long-term problems of technological improvements, market promotion and export strategy. Necessary action to implement the recommendations has been initiated.

(vii) Regional and international level consultations among the jute producing and jute consuming countries under the auspices of ESCAP, UNCTD and FAO are also being periodically held to formulate joint action programme to stabilise prices and export earnings of the jute producing countries.

(viii) Procurement of 1.98 lakh bales of B.T. Will bags through DGS&

D for April/June 1982 delivery on cost plus basis after linking it with purchase of 8 lakh bales of raw jute from JCI. This is in addition to the emergency purchase of one lakh bales of B.T. Will Bags during November-December, 1981.

These are the concrete steps which have been taken by the Central Government to help this industry. I hope that these steps will certainly help the industry. Now It is for the industry also to make use of these facilities given to them and to start the industry and to see that the workers do not suffer there. But, allow me, Sir, to say that it would be necesary for the workers also to take a stand which is helpful to the industry as such. If there is no understandings between the workers and the industry and the growers of jute it is going to be a difficult problem. And it is only by balancing the interests of the workers, the industry and the jute growers that this industry can survive and can prosper. If the balance is upset, the workers are going to suffer, the industry is going to suffer, and the growers are also going to suffer.

One of the ills with which this industry is suffering is non-modernisation and obsolescence. Unless that problem is overcome it is not going to be helpful. We have to see what can be done. As far as the Government of India is concerned, certain steps have been taken to help inmodernising. We have also seen that some sort of research is also started. After all these steps have been taken, we hope that this industry will come out of its difficulties, and would, after some time, at least start helping the export of this country as also the growers and workers in the industry as such.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, he has said about certain things in the Report. But am I to take it that the recommendations of the Task Force which were procesed by some Committee of Secretaries, as he mentioned have been, by and large accepted? What has happened to the recommendations? Have they been accepted? The question of implementation will arise later after these recommendations have been accepted, in the main. What is the position?

SHRI SHIV RAJ V. PATIL: At the appropriate time, we will certainly let you know. But the intention is to see as to how we can help the industry and there are certain recommendations which can be looked into and acted upon. There are certain suggestions which will not be possible for us to accept. But we will certainly let you know very soon as to what we are doing.

Sir, the second point which was raised by the 15th speaker related to the prices of the cotton. We have been told that this year the cotton that will be produced would be of the order of 17.50 lakh bales. The cotton which is produced in Maharashtra is procured by the monopolist scheme. I am told that 80 lakh bales were procured last year and this year 13 lakh bales have been procured.

MR. CHAIRMAN: Was it out of 17 lakh bales? What was the total production of cotton in Maharashtra?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Those figures are not with me. They have given the figures for the entire country as such.

Now coming to the market arrivals, in 1980-81, the market arrivals at that particular moment were 63.98 lakh bales. The market arrivals as on 13-3-1982 were 62.48 lakh bales. Now, the cotton purchased by the CCI this year has been 7.42 lakh bales. Thus the cotton purchased by the CCI is about 21 per cent of the cotton which had arrived in the market. Now, it was found that the prices were ruling quite high. They were higher than what they were last year. In the month of September 1981, the unit price was 240.3, when in 1980, it was 170. In October it was 232.2 and last year it was at that time 171. In November 1981, it was 225.2 and in previous year it was 178. Now, in December 1981, it was 227.7 and in the previous year if was 198.2. In January 1982, it was 225.1. It was provisional. In January last year, it was 205.3. In February 1982, it was 213.5 and last year during this period it was 206. So, the unit price of the cotton has always been higher than what it was in the previous year. In this month of March, 1982 this has come down and we have asked the CCI to step up the purchase of cotton and the

[Shri ShivRaj V. Patil]

prices have always ruled must above the support price. Now, what was the support Support price for Desi Kapas is Rs. 250|-; it was sold at Rs. 465|- this year and Rs. 415|- last year. Support price for J-34 was Rs. 304|-; this year on 31-3-1982 it was sold at Rs. 423|- and last year it was sold at a higher price. Support price for A-519 was Rs. 347|- and the price at which it was sold is Rs. 454|-. Support price for 1973 variety was Rs. 312|- and it was sold at Rs. 397|-. Support price for H-4 variety is Rs. 436|-, and it was sold at Rs. 487|-. Support price for MCU-5 was Rs. 453|- and it was sold at Rs. 437|-. Support price for Var Laxmi was Rs. 470|- and it was sold at Rs. 487|-. Support price for S-4 was Rs. 453|-, and it was sold at Rs. 471|-.

These figures go to show that the prices were much above the support price.

The Cotton Corporation of India has to do a twin duty, as I said last time also. CCI has to give at least the support price, or much above the support price, a sort of remunerative price—I would not call it a remunerative price pure and simple. At the same time, it is not the duty of CCI to see that the prices sky-rocket, and it becomes unremunerative for the consumers and the industry also to use cotton and to produce cloth. Here, a balance has to be struck. It is necessary to srike a balance between the consumers, producers of the cloth and the growers of cotton. Unless that balance is struck, it would not be possible to keep the industry going on, to give the remunerative prices to the growers of cotton and to see that the consumers get the cloth at a reasonable price. Here, also we do try our best and I suppose we will be able to cope up with any situation that arises with respect to cotton. If something needs to be done more than what we have done upto this time, we would certainly do this and we would not shirk our responsibility.

As far as the textile strike in Bombay is concerned, the Labour Ministry while replying to the debate on the Demands for his Ministry has explained the position taken by the Government of Maharashtra and this Government also. It would not therefore, be necesary for me to dwell in detail on the policy adopted by the Government of Maharashtra and this Government also.

I would, however, like to say that the strike is very, very unfortunate, and those who instigated this strike do not have the good of the labour at their heart. They are responsible for this strike, and all the Members have criticised those who are responsible for this. Yet, they are not appealing to the workers to come back. We appeal to the workers that they should come back to work; they should not succumb to the machinations of few persons, who have political ambitions, or who want to make use of the workers in that area. We would request them that they should see the writing on the wall, as to why those people are behaving like that and they should come back to the work. This Government has not been unresponsive to the real demands or the real needs of the workers, and we would not be wanting in future also. But, if somebody is trying to manipulate and somebody is trying to make use of the workers for something else, they should not fall a prey to that. There is a sort of consensus on this point in this House. Nobody has said that those who are responsible for this strike have acted wisely. Nobody has said in this House, from these benches and from those benches also. And I think that the patriotic workers would understand what is the meaning of the cosensus which has evolved in this House. Now, when we say that let us produce more, and somebody says let us not produce, let us strike; it cannot be patriotic, it cannot be beneficial to the workers. It cannot be beneficial to the others also. It is all right in Maharashtra there is monojoly procurement scheme. The cotton can be purchased over there. If it is not there then what happens to the growers of the cotton also?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Just a minute. Even imagining that under somebody's provocations 2.5 lakhs of workers have gone on strike, do you think that such a large number of workers can be provoked to remain on strike for more than 80 days without any genuine grievances? Therefore, would you assure to look into the genuine grievances

and try to find how about 2.5 lakhs of workers—and if you take their family into account, about 10 lakh family Members of the Textile workers—are prepared to starve for 80 days. If that happens, something must be pinching in their shoes. That is why they have succumbed to this particular leadership. Therefore, wise statesmanship should intervene in the matter and try to settle it for industrial peace as well as for justice to the workers.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, now here everybody agrees that those who instigated this strike did not act wisely. Now here everybody agrees that workers are suffering, yet they are not coming to the work. And why? Because the means which are used to keep them away from the factories are not acceptable to you and to us also and to anybody.

PROF. MADHU DANDAVATE: What are those?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The terrorist methods.

PROF. MADHU DANDAVATE: No, nobody has said this.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The fear psychosis that has been created.

PROF. MADHU DANDAVATE: No. They have gone back because of the dispute.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is not the individuals.

PROF. MADHU DANDAVATE: Do not go by the Police reports. Do not go by the labour reports.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is not the individuals. It is the tendency which has been precipitated over there, which has to be fought.

Now, the workers strike work because they feel there is somebody who can get something for them. And this kind of tendency can spread anywhere afterwards. That is why, When we are saying that we cannot be unresponsive to the difficulties of the workers, they should come back. I think they should come back. It is not the question of prestige with the Government; we should never stand on prestige on this point. What we are trying to do is not to accept a sort of tendency which in precipitating over there. Nothing more than that. I hope that workers would certainly understand and they would come back to work and the necessary protection will certainly be given to them by the Government in Maharashtra.

Sir, about the NTC some points were made by the Hon. Members. I am not saying that the NTC mills are earning profit and doing very well. One thing which should be understood about the NTC is that the NTC has taken over those mills which were sick, which were not running and which were kept close for three, four or five years. Those kinds of mills are taken over by the NTC and the NTC is running them.

Now, it has not been possible for the NTC to earn profit. True. But NTC is running those mills in order to give profit and this is also very important in respect of strike. When the textile industry is suffering and the textile mills are being closed, on the one hand we are trying to open the mills which are closed and run them, on the other hand we have somebody who is closing the mills or who is instigating the workers to close the mills which were working. The NTC has done its best to modernise. Sometimes it is said you modernise, but you are not producing more or you are not producing as much as you should have produced after investing these huge amounts of money. When the process of modernisation goes on, when a machine has to be removed and another machine has to be installed and when the time lag is there, It is not always possible to produce the requisite quantity of cloth from that mill. That aspect has to be considered. I would not say that everything is all right everywhere and all those things. That kind of sweeping statement I would not make. But these are the things which have also to be taken into account when assessing the performance by NTC.

About controlled cloth also, a statement was made. Four hundred ninety one million sq. metres of controlled cloth

[Shri Shivraj V. Patil]

we have produced in 1980-81 and we have produced 287 million metres of Janata cloth in 1981. We are giving a subsidy of Rs. 76.50 crores on controlled cloth, and of Rs. 44.86 crores on Janata cloth. I think there is enough of controlled cloth and Janata cloth. That cloth is distributed by NTC. That cloth is given to cooperative societies, and it is given to people who are living in the villages and it is purchased by them.

About the quality, there are complaints. Because the price difference between the controlled cloth and the Janata cloth, and the cloth which is available outside is reduced because of the new policy which we have adopted, people think that if the cloth outside in the market is available at a particular price which is slightly above the price at which the controlled cloth and Janata cloth are available, the quality of this cloth should also be good. This is the difficulty. I think we will be able to overcome that also after some time.

As far as handloom is concerned, a very lucid speech was made by the hon. Member over there; but I would like to bring to his notice that on handloom about Rs. 20.79 crores were spent in 1981-82. In 1982-83 we are intending to spend about Rs. 23.42 crores. The total Plan outlay in the 5th Plan in the Central sector was Rs. 37.30 crores; and on the State sector Rs. 62.62 crores, and the total outlay was to the tune of Rs. 99.92 crores. That was for the 5th Plan. In the 6th plan, the Central sector will be spending about Rs. 120 crores, and the State sector about Rs. 190.93 crores. The total would be Rs. 310.93 crores. This is the amount which we are going to spend on handloom. If this is the amount which we are going to spend, I think you would not blame the Government for not having paid sufficient attention to the problems of handloom, and for not having provided sufficient money for that purpose. The subsidy provided on Janata cloth in 1981-82 was Rs. 44.86 crores and in 1982-83 this is going to be R 53.75 crores.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why have you landed only the NTC with this controlled cloth? Formerly there was a quota for the private mills also. But they did not want to make it. So, you obliged them by releasing them from that obligation.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Central Government is taking the social obligation on itself. If you are blaming the Government for taking on itself this social obligation, I do not know how this problem should be solved. If somebody is not prepared, if somebody has not produced, and if the NTC mill has produced or if the decentralized sector, viz. the handloom sector has produced, I think there should be no objection to that. I am saying that we can ask NTC to produce for the Government; we can ask NTC to produce for the people who cannot afford to purchase cloth at higher prices. We can ask NTC to produce for export also, along with others. In this fashion, we can make use of the mills which we have taken over; and we can utilize the capacity which is avaliable with them.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Don't expect them to make profit in that case.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: As far as trade with Latin America is concerned, I will have a talk with my learned friend; and we do think that we should increase our trade and commerce with Latin America also and all the steps which are necessary for this propose should be taken. As far as rice bran extraction is concerned, I would not like to comment on it. As far as tanning the industry is concerned, the hon. member had a talk with me and I would not like to dwell upon that aspect also. I would like to come to the trade deficit.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: What are you going to do with sugar?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will talk to you.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Please call him to your chamber.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: All right, I will come to your chamber.

PROF. MADHU DANDAVATE: He is prepared to go to the gas chamber also.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Hon. members have expressed their concern about the trade gap. Of cource the trade gap is increasing. Why is the trade gap increasing has to be seen? Hon. member Shri Indrajit Gupta and others said that it is increasing; the Minister would stand up and say, it is increasing because of POL. I shall have to say that, I have no other option; I shall have to make that statement on the Floor of the House. I would like to tell you some aspects relating to the import of POL. Now, there is a hike in POL price. This has risen 21/2 times within a short period of three years. The deficit of the foreign trade for the year 1980-81 barely comes to Rs. 203 crores excluding the bill of import of POL in 1980-81. The deficit would be of only Rs. 203 crores if you exclude the import bill of POL from the entire import bill. If you calculate arithmetically, you will come to that conclusion only. Now the import of POL, fertiliser and non-ferrous metal and the iron and steel which are essential inputs into domestic production account for 60 per cent of the total import of 1980-81. Now, what is it that we are importing? We are importing POL, fertiliser, non-ferrous metal, iron and steel and all these are essential inputs. We are not importing Impala cars; we are not importing fancy goods; we are not importing luxury goods like the refrigerators and things like that. Now, all these things are required for supporting our industry. Steel is required for our industry. For, instance, fertiliser is there. Do you want that we should not import fertilisers even if they are required? Without fertiliser, it will not be possible for us to have agricultural production going up every year. Without fertiliser, it will not be possible for us to produce more rice, more wheat, more sugar and all those things. You say, we should produce fertiliser more. For your information, may I say that the production of fertiliser last year has gone up by more than 50 per cent; even then our requirement is not met by the indigenous production. It would be necessary for us to import fertiliser. If we are asked that fertiliser should not be imported, then we will be asking that foodgrains should be imported from outside.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It was a member from your side who said that the fertiliser which had been imported, the bulk of it is still lying in stock and it has not been lifted. There is no proper co-ordination between the requirement and the import.

SHRI SHRIVRAJ V. PATIL: That is not a fact. If a member from this side speaks something, it does not mean that every information is at his finger tips and he is in a position to know everything and speak out. Now, from that side also a member can commit a mistake. A member from this side may not be equally informed about it.

What I am trying to say is that these are things which we are importing. And if these things are required, it would be necessary for us to import these things and then give a sort of support to our agriculture and industry also. An hon. Member from this side said that 'you are importing diamonds'. Well, we are importing diamonds. But we are not importing diamonds in order to make use of them in our country. What we do is, we import the diamonds, the diamonds are cut, jewellery is made and the jewellery is sent outside the country which earns foreign exchange which is required by us. Now, if we do not understand this aspect of the import of diamonds, we are likely to commit a mistake in assessing the policy which is adopted by the Government. Simply saying diamonds are imported. Well, it is factually correct. But diamonds are imported not for retaining them: diamonds are imported, after cuting them and making the jewellery, that jewellery is sent outside.

Now this deficit can be reduced. What is the methods which we want to adopt for reducing this deficit? Our policy is directed at producing more, for our internal consumption and when we produce enough that can be exported to other countries also and that would help us in reducing the gap which is already there.

[Shri ShivRaj V. Patil]

Now, we are emphasising on the production of POL also in our country. All steps which are necesary for this purpose are being taken. We are taking steps to see that fertilizers are also produced; and by producing fertilizers on a very large scale, by producing P.O.L. on a large scale, by making the industry produce the goods which are necessary for ourselves and for exporting also, we would be able to reduce this gap. Apart from this, the policy which we want to adopt for giving a fillip to the export is this. Facilities are provided for increasing the production of perishable agricultural commodities including fruits and fresh flowers for which there is a buoyancy in the foreign demands; simultaneous efforts will be necessary to provide the necessary refrigeration and quick transport facilities. Hon. Members said that this kind of thing should be done. We have already decided that something of this nature has to be done and we would certainly be doing that.

Coming to increasing exports by Public Sector Undertakings, we are asking the public Sector undertakings also to produce enough to that the surplus can be exported and to ensure larger participations in exports and projects of construction and consultancy services for which there is a large scope and adequate facilities are available in the country. We have lot of manpower and skill in our country. That manpower and skill can be utilised in other countries and those gentlemen who would be going abroad will see, and the skill which we have, for production, will be able to earn foreign exchange for our country to increase the production of engineering goods and other manufactured products including electronic goods, as the world demand of these items is increasing.

Coming to enlargement of agricultural production and facilities for export of value added agricultural products, while speaking on this subject, an hon. Member said that even if there is some sort of deficiency in a particular grain in our country, if we have enough grain in our country, let us export that. In the policy which was enunciated in 1970 it was decided by the Government that at the time of creating capacity for production we should take into account the capacity required for producing enough to export also. And at times when it is possible and feasible we should export even when we do not have sufficient things, things sufficient for ourselves internally. That is the policy which we have adopted. But this can be done in a very discreet manner. This cannot be adopted as a policy which has to be adopted and implemented without taking into account the requirements of our people also. About sugar, if we have sufficient sugar it may be that we will be able to export sugar. But supposing we are not having rice, or we do not have wheat, then should we export rice and wheat also? Now if the requirement is not very pressing in our country and we can adjust a little bit here and there we would be exporting them. But this kind of deision has to be taken after assessing situation, which is available in the country.

The exploration of new markets and new products for exports and greater involvement of the State Governments in the efforts are necessary. We are involving the State Governments also in exports. Further streamlining and simplification of export procedure and documentation, provision of market information to the exporters by improving the commercial intelligence service and information system, these are the steps we are trying to take, and we hope that it would be possible for us to give a fillip to the export which we want to do from our country.

We think it would be possible for us to reduce the trade gap which is existing. The most important thing which is to be done by our country to reduce the trade gap is to produce more oil, fertilizers, steel and machinery. If we are successful in producing sufficient quantity of oil, sufficient quantity of fertilizers and machines, it would be possible for us to reduce the gap. It is not by restricting the imports of small things that it would be possible for us to reduce the gap.

We shall have to understand that about 70 per cent of our foreign exchange expenditure is consumed by POL, fertilizers and machinery. If we really want to reduce the gap, it is this area in which we have to work. If we do not pay attention to this area, if we give up attempts in this area and try to do something else, or just restrict import of some of the minor items, it is not going to be possible to reduce the gap. So, the Government is very clear in its mind where it should give emphasis and where it should not attach that emphasis. Government is very clear on that and is doing everything possible for that purpose. If the trade gap has increased, should we be unhappy all the time ? Is trade gap everything? I am not saying we should subscribe to continued trade gap or that kind of thing; I am not saying that. But we shall have to take into account how the imports have helped us in increasing production in our industries, in increasing production in our agriculture. If there we have been successful, if we were able to do that, then we need not worry unduly. One of the members on the last day asked me a question by saying: last year you liberalised imports and you thought you would be able to reduce the gap ; have you been able to do that? That was the question put to me. I would like to say that the production from industry has gone up by 10.5 per cent, Further, we are not importing luxury goods. We are importing the inputs, the raw materials, necessary for this purpose. Without raw materials you will not be able to produce anything. You have the industry and you have the capacity. If that capacity is not utilized, what is the use of having that capacity? If the raw material is not available, what is the use of having the industry, what is the use of having the capacity? Our intention is, now that we have created this capacity, this industrial capacity, it would be necessary for us to feed that industry to produce. If the raw material is available in our country to feed that industry, that will be supplied. But, if that kind of raw material is not available in our counry, it would be necessary to import it from outside to feed that industry to produce enough for our people and enough for others also.

It is not only the trade gap which has got to be kept in mind. I am not saying for a moment that it is not the duty of the Commerce Ministry to reduce that trade gap. We will be able to succeed tea very great extent in reducing the gap. But that is not the thing. The overall economy has to be taken into account. It is only after taking a view of the entire economy as such that we would be able to say whether the policy, which is formulated and followed by the Government, is correctly formulated and correctly followed or not. If we do not take that into account, we are likely to commit mistakes as to the correctness of the policy or otherwise.

SHRI INDERJIT GUPTA: Why in the new import policy there is a departure in licensing? Previously, the import licence was strictly confined to the actual users. Now you have made it available for non-users also.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am coming to that point. I have beard your speech very attentively and I have jotted down every point. I would be coming to that.

SHRI INDERJIT GUPTA: Jotting down does not mean anything.

SHIVRAJ V. PATIL: I will explain it, You shall have to wait a little.

Sir, about the import and export policy, I think the import and export policy which was enunciated by the Government and which was declared to the people in our country is welcomed by many of the people here. Of course, there have been some dissenting voices and people have criticised that policy also, as was done by the hon. Member, Shri Gupta.

What is the aim of this import and export policy? The aim or the object with which this policy is formulated is to produce more and we want to produce more and export. The second object is to modernise. Sir, modernisation is very very important. If we produce the goods which are not acceptable in the outside world, we shall have to consume them here. With those goods it would not

[Shri Shivraj V. Patil]

be posible for us to earn any foreign exchange. Not, in the outside market there is a very stiff competition going on. If you produce cloth which is competitive cost-wise and quality-wise, it would be purchased. If it is not competitive, it may not be purchased. There may be a market, in that market there may be a lot of funds and in that market may be people who would like to help you also. But if the quality of your goods is not competitive, then they would say 'All Right, we will look to your goods a little later, we will like to purchase other goods.' Our intention is to give capacity to our people to produce the qualitative goods. For this purpose we are allowing some of the industries to import the machinery.

Then a partinent question was put by hon. Member, Shri Gupta. Gupta Ji wants to know as to why the actual users and others also are allowed to import the things.

SHRI INDERJIT GUPTA: The question of actual users is all right, but I am asking about the non-users.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: All right, I can explain this point to you. What used to happen previously is, there were small industrialists and they required certain raw materials for their industries. They used to take licences from us and it was not possible for them to import items required for their industry from outside. What they used to do is, they used to collect those licences, give them to somebody and ask him to import it. The time required for this purpose was consumed and they were not able to get the requisite quality and quantity of the raw material for their industry. Our intention in making a provision of this kind is that if there are small-scale industrialists, they would get the permission to import the things and they will be given to the small-scale industrialists. The only important intention behind this kind of policy is to help the small-scale industrialists. Do you want us to help the small-scale industrialists or not? Do you want that they should go from pillar to post asking for the raw material and they should not be able to get the raw material in time and their industry should suffer?

SHRI INDERJIT GUPTA: It is to create some private middleman—a private middleman who will import and then give it to the small men.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is one of the reasons why this kind of policy is made.

MR. CHAIRMAN: One thing which he wanted to know is that no-users just to help the small-scale industrialists are permitted now to import.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes.

SHRI INDERJIT GUPTA: That is the only purpose?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Which will be the agencies who import?

You allow the STC.....

(*Interruptions*).

SHRI SHRIVRAJ V. PATIL: Now also STC and other Corporations which we have with us are also allowed to import certain of the items. Sometimes what happens is, when they have to import such items, there is some kind of time gap and you shall have to take into account the machinery required for this purpose. Ours is a very vast country, there are small-scale industries in every nook and corner of this country at district level and at taluk level and you want the STC and the Corporations which are working with us to cater to all the demands that they put forth. If this is the kind of machinery if you want us to try and create, we can create. But the overhead expenses which are required for this purpose will be too high. So, we are trying to strike a balance. We are asking our Corporations to import. We are also asking others to import and to make these raw materials available to the small scale industries.

SHRI SOMNATH CHARTERJEE: What will be the consumer price and the regularity of supply? Would they supply or not?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: It is only those who are making use of these things who are getting. To say that this kind of facility should not have been extended, would go contrary to the interests of the small scale industrialists. We do have the interests of the small scale industrialists at our hearts and we have taken this steps to help them. I hope, this would be appreciated by the small scale industrialists and this will be appreciated by the hon. Member, Shri Gupta also after this explanation. What I am trying to say is this. We are not importing any fancy goods. What is being imported or what is allowed to be imported is only input and raw material. Sir, we have to understand this aspect. Now, even the developed countries are importing inputs and raw materials from other countries. Here is a country which is a developing country and having produced the industrial capacity, it is importing raw materials to feed that industry. Can you have any objection to that? I do not see any objection to that.

SHRI INDERJIT GUPTA: Why don't you import it yourself? Why do you want to create a new party, middleman?

MR. CHAIRMAN: He has explained. He has said the overhead would be much more and it will not be possible to supply. You may agree or disagree.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It would lead to black-market and dealings under the table (*Interruptions*).

SHRI INDRAJIT GUPTA: All right, Let us see.

SHRI SHRIVRAJ V. PATIL: Then, Sir, comes the simplification of procedure. The new policy has simplified the procedure and it is formulated with an intention to help the small scale industries. Our emphasis, we have underlined with a red pencil, is that we have to help the small scale industries to produce more and for exporting also. With this aim, this policy has been formulated.

I am very happy to note that some of the hon. Members who might be criticising it openly but in their heart to heart, they are also appreciating.

(*Interruptions*).

There were some Members who have told me that I have not liberalised enough. Well, we have not liberalised enough. We cannot liberalise to import the luxury goods. We cannot do that. We have liberalised sufficiently to see that our industries prosper, our industries produce enough goods. This kind of liberalisation is there. Neither this policy is restrictive nor is it liberalised completely. It is only helpful. It is going to be helpful to the small scale industrialists it is going to be helpful to cut down the red tape and the procudure involved in it and it is going to be helpful to produce more and more for export. It is only with this intention, this has been formulated.

Some hon. Members got up and said this policy was formulated under the pressure of IMF. Well, my learned friend and colleague here, in a very short but in a very beautiful speech, has said that it has become the latest fashion to mention IMF and to say that the Government of India is working under IMF presure. (Interruptions).
I do not understand what is wrong in importing raw material for the industries, what is wrong in importing the machinery required to cut down the price on the petroleum products and on the energy.

We want to modernise it and to see that the cost and the consumption of the power is reduced, to see that the time is reduced, and to see that the quality goods are produced. With this intention, we modernise our industries and if the technology is not available here, we get it from outside. You say, it is at the cost of our industries, at the cost of our technology, we are doing it. We are not doing that. We get a clearance from our indigenous industries angle and only then, we import. If this is our intention, what is wrong with it?

[Shri ShivRaj V. Patil]

SHRI INDRAJIT GUPTA: Have we not the technology in this country to make tooth paste ? Have we not the technology to make biscuits?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Let us understand. We are not going to import technology for this purpose. Even if we import technology for this purpose it will be for export purposes and not for the local consumption.

Let us understand that. We are living in a world which is shrinking. Everywhere, in every nook and corner of the world, research is going-on, development is going on, and the people are creating a new kind of technology and machinery. Should we not make use of that new technology that is available there? We have also done a lot of things in the development of technology. We would also help them. Should we not make use of that? Should we start from the scratch, from the beginning right from ABC, first develop technology and then develop machinery ? And until that machinery is developed, should we wait ? This kind of policy, this kind of philosophy, in a world of today where we are trying to create a new economic order cannot be acceptable.

Of course, we will not go against our interest; we will not bend before anybody; we will not work under any pressure from anybody. The hon. Members should understand that India is too big a country and too powerful a country to be cowed down by anybody, to be dictated to by anybody. No body has been able to do it; no organisation has been able to do it; no country has been able to do it. Please for God's sake, don't lose confidence and abuse the Government all the time saying that this Government is working under pressure of anybody. If any good sugegstio nis coming from anybody, should we not accept it? It may come from south; it may come from north; it may come from east; it may come from west. Should we not accept it? If you just say that IMF if there and that we are working under their pressure—you can go on saying that—I would supply say that that it is not at all correct: It has been refuted by the present Finance Minister and it has also been refuted by the Prime Minister. I also refute that kind of an allegation.

I would say that our import policy, the liberalisation of import policy, if it is a liberalisation, is relaxed a little which will help our industry also. It is not under anybody's pressure. Please for God's sake, don't think that the Government is working under anybody's pressure. After all, the Government is representing the entire nation as such. Don't lose confidence in yourself and don't think that your brothers will give in to the pressure....

SHRI INDRAJIT GUPTA: Please don't bring God into this controversy.

PROF. MADHU DANDAVATE: If you say, for God's sake, Shri Indrajit Gupta will be exempted!

SHRI INDRAJIT GUPTA: What will happen to our own domestic machinery building industry?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have answered that point.

SHRI INDRAJIT GUPTA: You have not.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We are going to spend on research and development; we are going to spend on the development of machinery in our country. The industry which produces machinery will be given all sorts of impetus. But, at the same time, if that kind of machinery cannot be produced in our country, I hope, you will not expect us to wait until the time the research is developed, the formula is found, the machinery is developed and the production is started. That is not our expectation. I have said that, after getting the clearance from the indigenous industry point we will do that. Otherwise not. It is only when the indigenous industry says that it is not possible to produce it, we will do it. Not otherwises.

A reference was made to the North-South dialogue, the South-South dialogue, the Melbourne Conference and all those things. I think we are trying to create an atmosphere in the world itself which is helpful to everybody....

SHRI INDRAJIT GUPTA: I approve of them; you have misunderstood me.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am not replying to you. I am replying to the point that some one else made in that regard. Some one asked what we have got from those conferences and all that. This is the position.

Then, a question was put by my hon. friend, Shri Indrajit Gupta. He was wanting to know, when this kind of world situation is there, how we are going to cope up with the problem of deficit in exports. I have explained what will be our direction and how we will be able to try to overcome that problem. I know, the world situation is quite gloomy; there is recession in the world; of course, the inflation is also there and the world situation is not helpful. But I am sure, we have faith and confidence in our people, in our system and in our policies.

17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

And I hope that we will be able to do it. Some hon. Members were saying that the rate of growth in export was only four per cent. It is not four per cent; it is much more than that; it is, I think, 15.2 per cent in 1981-82. The hon. Members were referring to the last year's. 1981-82 is the relevant period. The rate of growth of import has also gone down substantially from 38 or 39 per cent. That is what we have achieved. Of course, much has been achieved and much remains to be achieved. We are not going to be complacent; we are not going to rest on our oars; we will be doing our best to see that this deficit is reduced.

I would again like to thank all the hon. Members who were very constructive in their approach. Some of the criticisms levelled by them may not be acceptable to us, but I could see that they have their own philosophy, their own thinking and, therefore they speak out of that. I think, the debate on the Demands for Grants under the control of this Minstry was really very constructive, informative and instructive. I would again like to thank all the hon. Members and request the House to vote the Demands.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I seek a clarification? I am only trying to find out whether the hon. Minister remembers that he has an organization under his Ministry called the National Jute Manufacturers' Corporation....

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is a new point. I am ready to talk to him if there is any problem.... *(Interruptions)*

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I have written to him, I have written to his predecessor, Shri Pranab Mukherjee. He has been promoted but the NJMC has been demoted. Since nationalisation, it has been incurring losses. There is complete chaos in the management, there is nepotism, there is corruption. I have brought it to the notice of the hon. Minister, but I am very sorry to say that not even an acknowledgement has come. It seems—I have said in another letter which I have sent to him—that the officials under the management of the NJMC seem to be above everybody, they just do not bother....

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is a new point he is making.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am bringing it to your notice. You are so much enamoured of your new liberalised import policy that you are not thinking of the other organizations. This is a very important matter. The jute mills which are now under the control of the NJMC, are in complete doldrums because of the inept management, corrupt management..

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Indrajit Gupta has already raised it.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I said the same thing about the eastern regional subsidiary of the NTC to which also he did not reply.

SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Should we start another debate on this?

SHRI SOMNATH CHATERJEE: I am seeking a clarification with the permission of the Chair.

Would you believe, Sir, if I say that these nationalised jute mills continue to

[Shri Som Nath Chatterjee]

be affiliated to the Indian Jute Mills Association which is an organization of the big jute barons? Until recently, they continued to be so. This is the position.

Recently, some representatives of European countries came on a purchase mission; they wanted to purchase jute products from here, but they did not purchase even one ounce from the NJMC mills because nobody went and attended to them. Only the private mill-owners have been able to enter into contracts with them.

It seems that today he does not know anything, he is completely blank. He is busy with his liberalised import policy now. Therefore, I request him to look into this matter. I have sent the papers to him. Let him give an assurance on the floor of the House that he will himself look into it or his able Deputy will do it— I am very happy with Mr. Sangma.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I would like to say that I do not know whether I have received his letter or not. I do not remember it. But generally my policy is that, the day I receive a letter, I send the acknowledgement and after examining it, we give the information. I would try to find out if that letter is there and I would certainly reply to it if it is there. This is a new point. Even then, even if I do not give an assurance on the floor of the House, I think, it is a part of my duty to look into such matters if there is anything wrong. I will certainly do it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Commerce to vote together unless any hon. Members desires that any of his cut motions be put separately.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Commerce to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Accounts and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1983, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 11 to 13 relating to the Ministry of Commerce."

The motion was adopted.

Demands for Grants (General). 1982-83, in respect of Ministry of Commerce voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16th March, 1982		Amount of Demand for Grant to voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF COMMERCE					
11	Ministry of Commerce .	35,08,000	..	1,75,40,000	..
12	Foreign Trade and Export Production . .	127,68,29,000	18,16,76,000	465,91,,43,000	90,83,81,000
13	Textiles, Handloom and Handicrafts . . .	36,91,39,000	7,96,10,000	132,06,97,000	39,80,50,000